राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 2 सितम्बर• 2025
www.rashtriyasahara.com

संभावनाओं भरी मुलाकात

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर तियानजिन में हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात से भारत में उत्साह का माहौल है। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर ही अधिक केंद्रित रही। पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में इतना तनाव आ गया था कि मोदी और शी की मुलाकात से ही उम्मीदें जगने लगती हैं। मोदी 2020 में हुए इस विवाद के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। हालांकि दोनों नेता पिछले साल रूस के कजान में भी मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छेड़े टैरिफ 'युद्ध' से मची उथल-पुथल के बीच बेहद सावधानी से हुए संवाद में दोनों नेताओं ने खूब अच्छी अच्छी बातें कहीं। मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान एवं संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि सीमा प्रबंधन पर भी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए, दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन का विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी शिनफिंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि दोनों देशों का 'मित्र' बनना सही विकल्प है तथा 'हाथी (भारत) एवं ड्रैगन (चीन)' को एक-दूसरे की सफलता का मिलकर जश्न मनाना चाहिए। चीन और भारत एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। दुनिया इस समय ऐसे बदलावों से गुजर रही है जो सदी में एक बार होते हैं। मोदी और शी की मुलाकात पर सवाल भी उठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मेना प्रमुख ने लद्दाख में सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मोदी भारत चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इससे उस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को अप्रत्यक्ष रूप से बैधता मिल गई है। लगता है इसी साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी को क्या हमने भुला दिया है। कुल मिलाकर जहां यह माना जा रहा था कि यह मुलाकात ट्रंप को करारा जवाब देने का मार्ग प्रशस्त करेगी तो इस बारे में साफ-साफ कोई रणनीति नहीं बनी है। कारण यह कि भारत रूस-चीन को साधना चाहता है तो अमेरिका को भी।

प्रशंसनीय पहल

उत्तर प्रदेश में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए योगी सरकार का ऐलान वाकई सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 1 अगस्त से 'हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं' का विशेष अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। यह विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितम्बर तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। दरअसल, देशभर में बिना हेलमेट लगाए बाइक चालकों की मौत का आंकड़ा व्यापक है। देश में साल 2021 में हेलमेट न पहनने के कारण लगभग 47,000 लोगों की मौत हुई, जो कि हर घंटे चार लोगों की मौत के बराबर है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और हेलमेट न पहनने के खतरनाक परिणामों को दर्शाते हैं, खासकर दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए, जहां मौतें अक्सर हेलमेट के इस्तेमाल से रोकी जा सकती हैं। राज्य सरकार के इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मगर सड़कों पर कुछ दिनों के अभियान के बाद हालात पहले की तरह लापरवाही भरे दिखने लगते हैं। कई बार तो जुर्माने से बचने के लिए युवा तबका बाइक को ज्यादा तेज गति से भगाने लगता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। शायद इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि इसका लक्ष्य नागरिकों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईथन तभी, जब हेलमेट सिर पर हो। बहरहाल, सरकार को इस नियम को कायदे से लागू करवाने के लिए जरूरत से ज्यादा मशक्कत करने की कवायद करनी पड़ेगी। काफी अरसा पहले दूरदर्शन में हेलमेट की महत्ता और लोगों की जान की कीमत को लेकर एक विज्ञापन दिखाया जाता था। वैसे भी एक बात सभी को समझानी चाहिए कि बिना सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किए कोई भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए कार सवार के लिए सीट बेल्ट और बाइक सवार के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जीवन रक्षा की गारंटी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला निःसंदेह प्रशंसनीय है। हालांकि ऐसे अभियान की सफलता तभी कारगर है जब पब्लिक नियम-कायदे का पालन करे और अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए बाकी लोगों को भी जागरूक करे।

नारियल दिवस/श्वेता गोयल

विकास का आधार

हर वर्ष 2 सितम्बर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह अवसर न केवल नारियल जैसे बहुमूल्य फल और उसके वृक्ष के महत्व को समझाने के लिए है बल्कि यह दिन दुनियाभर के लोगों को इसके पोषण मूल्य, आर्थिक महत्व, खेती, प्रसंस्करण, उपयोगिता और वैश्विक स्वास्थ्य तथा कृषि में इसकी भूमिका को याद दिलाने का भी माध्यम है।

यह दिवस दुनियाभर में लोगों को नारियल के फायदे समझाने, नारियल के पोषण मूल्य और आर्थिक महत्त्व के बारे में बताने, नारियल की खेती, प्रोसेसिंग और इसके कई उपयोगों के बारे में लोगों को शिक्षित करने, वैश्विक स्वास्थ्य और कृषि में नारियल की अहमियत समझने, नारियल से जुड़े नये तकनीकी तरीकों को अपनाने, नारियल से जुड़े उद्योगों में मौजूदा चुनौतियों को दूर करने इत्यादि अनेक उद्देश्यों के साथ 'एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय' (एपीसीसी) के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस संगठन का उद्देश्य नारियल से जुड़ी हर गतिविधि को बढ़ावा देना, नारियल किसानों की स्थिति में सुधार करना और नारियल उद्योग की मजबूती के लिए प्रयास करना है। दुनियाभर के लगभग 80 देशों में नारियल की लगभग 150 किस्में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती सबसे अधिक होती है और लाखों किसानों की आजीविका इसी पर आधारित है। नारियल को यूं ही जीवन का वृक्ष नहीं कहा जाता। नारियल के आर्थिक महत्त्व की बात करें तो यह किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। लाखों छोटे किसान अपनी रोजी-रोटी नारियल की खेती से चलाते हैं। इसके अलावा नारियल से जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों में भी रोजगार के व्यापक अवसर मौजूद हैं। नारियल तेल, नारियल दूध, नारियल पाउडर, कोयर उद्योग, हस्तशिल्प, बायोफ्यूल और सौंदर्य उत्पाद जैसे कई उद्योग सीधे-सीधे नारियल पर निर्भर हैं। यही कारण है कि एपीसीसी जैसे संगठन नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में जुड़ी तकनीकों के विकास और प्रसार के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीकें न केवल उत्पादकता को बढ़ाती हैं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती हैं।

बदलाव की बह रही बयार

बिहार में महिलाम्मुखी नीतियां

डॉ. दर्शनी प्रिय

बिहार अपनी बदली आबोहवा में नये प्रयोगों के जरिए नई पहचान बना रहा है। पिछले पंद्रह वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में महिलाओं को केंद्र में रखकर ऐसी अनेक योजनाएं बनी जिसने इस सूबे की स्त्री हितैषी तस्वीर खींची, चाहे स्कूली लड़कियों को साइकिल देने की बात हो या शराबबंदी या अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इन सबमें कहीं-न-कहीं राज्य की एक कल्याणकारी तस्वीर प्रतिबिंबित होती रही। इसने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए बदनाम इस राज्य की तस्वीर बदल दी है।

आज स्थिति यह है कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में मिसाल बन रहा है। इसका श्रेय निश्चित रूप से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी नीतियों और उसके क्रियान्वयन को जाता है। साल 2005 से लेकर अब तक सरकार ने महिलाओं के प्रति किए अपने वादे के प्रति कटिबद्धता दिखाई है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में मजबूत बनाने के इनके एजेंडे को भले ही शुरुआती दौर में थोड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी हों, लेकिन धीरे ही सही अब वादे फलित हो रही हैं। यदि गहराई से इसकी पड़ताल करें तो सरकार की मौजूदा योजनाएं न केवल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और लिंग समानता को भी बढ़ावा देती दिखती हैं। आधी आबादी की सलाहियत और हित को ध्यान में रखते हुए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' जैसी पहल इस दिशा में एक नया अध्याय जोड़ रही हैं।

महिलाओं की प्रगति और विकास के लिहाज से इन योजनाओं की फिरे से पड़ताल भी जरूरी है। खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में इन योजनाओं से क्रांतिकारी बदलाव लाया है। 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' को एक ज्वलंत उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत साल 2006 में तब हुई, जब सूबे में लड़कियों की स्कूल ड्रॉपआउट दर बहुत अधिक थी। योजना के तहत, कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली हर लड़की को मुफ्त साइकिल प्रदान की गई, ताकि वे दूर-दराज के स्कूलों तक आसानी से पहुंच सकें। इसका परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की नामांकन दर में 30 फीसद से अधिक की वृद्धि हुई। आज, लाखों लड़कियां इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इसी क्रम में, 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' 2018 में शुरू की गई, जो लड़कियों को जन्म से स्नातक स्तर तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत, जन्म पर दो हजार रुपये कक्षा एक से बारह तक विभिन्न राशियां, और स्नातक पर पच्चीस हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना से अब तक करोड़ों रुपये वितरित हो चुके हैं, जिससे लड़कियों की शिक्षा दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान दिया है। 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना) इस साल 2007 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और बाजार पहुंच प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत, महिलाओं को बैंक से लिंक किया जाता है, जहां वे बचत खाते खोलती हैं और सूक्ष्म ऋण प्राप्त करती हैं। आज, सवा आठ लाख से अधिक एसएचजी समूह बने हैं, जो 80 लाख परिवारों को कवर करते हैं। इन समूहों ने महिलाओं को कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों में संलग्न किया है। जीविका दीदियां अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम करती हैं और 'दीदी की रसोई' जैसी पहल ये सरकारी संस्थानों में भोजन उपलब्ध कराती है। इस योजना का प्रभाव इतना गहरा है कि गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य इसे अपना रहे हैं। जीविका ने महिलाओं की आय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि की है और उन्हें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। अभी हाल ही में शुरू की गई 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, हर परिवार से एक महिला को प्रारंभिक किस्त के रूप में दस हजार रुपये दिए जाते हैं, जिससे वे कोई छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सकें। छह महीने बाद, सफल प्रदर्शन पर दो लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी महिलाओं को लक्षित करती है, जिनकी आय सीमा निर्धारित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होगा। इसी दिशा में और भी कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिसने महिलाओं को विकास के लिहाज से मजबूती प्रदान की है। साल 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया, जिससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसी तरह, 2007 में नगर निकायों में भी पचास प्रतिशत आरक्षण दिया गया। साल 2016 में, सरकारी नौकरियों में पैंतीस प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया, जो पुलिस से लेकर प्रशासनिक पदों तक लागू है।

इसके अलावा, राज्य न्यायिक सेवाओं में पचास प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई, जिसमें अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त कोटा है। इन नीतियों से महिलाओं की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका मजबूत हुई है। 'महिला थाना' योजना के तहत, हर जिले में महिलाओं के लिए विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जहां महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। पैंतीस प्रतिशत पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया, और 'स्वाभिमान बटालियन' जैसी इकाइयां गठित की गईं। इन योजनाओं का समग्र प्रभाव बिहार की महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया है। निश्चित ही महिलाओं के हित में उठाए गए क्रांतिकारी कदम इस बात की तस्दीक करते हैं कि मौजूदा राज्य सरकार महिलाओं के विकास को लेकर उदार रवैया अपना रही है। एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में निश्चित ही बिहार भविष्य में एक उदारवादी सूबा साबित होगा, इसकी अपेक्षा है।

(लेखक बी.बिकार विश्वविद्यालय)

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' व अन्य योजनाओं का समग्र प्रभाव बिहार की महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया है। निश्चित ही महिलाओं के हित में उठाए गए क्रांतिकारी कदम इस बात की तस्दीक करते हैं कि मौजूदा राज्य सरकार महिलाओं के विकास को लेकर उदार रवैया अपना रही है। एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में निश्चित ही बिहार भविष्य में एक उदारवादी सूबा साबित होगा, इसकी अपेक्षा है

देश के एक तिहाई स्कूली बच्चे लेते हैं निजी कोचिंग

- देश के करीब एक तिहाई स्कूली बच्चे निजी कोचिंग का सहारा लेते हैं। यह प्रवृत्ति शहरों में ज्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर शिक्षा सर्वेक्षण (सीएमएस) में यह खुलासा हुआ है
- सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकारी स्कूल पूरे भारत में शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और देश के विद्यालयों में नामांकित कुल छात्रों में 55.9 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकारी विद्यालयों की है
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा पिछला व्यापक शिक्षा सर्वेक्षण (75वां दौर) जुलाई, 2017 से जून, 2018 के बीच किया गया था

(स्रोत : मीडिया रिपोर्ट्स)

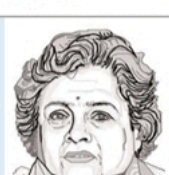

कूटनीति की बलिहारी।
जिस लाल कालीन पर भारत का स्वागत हुआ, उसी पर उसके पुराने दुश्मन का भी किया गया, क्योंकि उनने नट की चुतराई से चीन और अमेरिका दोनों को अपने हित में नाथ लिया है।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

डॉक्टरों के पर्चे डॉ. सत्यवान सौरभ

लिखावट पर अदालत की फटकार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया है, जो न केवल हरियाणा-पंजाब बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टरों को अब मरीजों की पर्चा साफ लिखनी होगी। बेहतर होगा कि डॉक्टर अपनी लिखावट कैपिटल लेटर्स में करें या फिर टाइप/डिजिटल रूप में पर्ची दें। यह फैसला सिर्फ लिखावट की अौचारिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे मरीज की सुरक्षा और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़ा हुआ है।

भारत में अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि डॉक्टरों की लिखावट इतनी उलझी होती है कि फार्मासिस्ट या मरीज को समझ ही नहीं आता कि कौन-सी दवा, कितनी मात्रा में और कितने समय तक लेनी है। ऐसे में गलत दवा या गलत खुराक से मरीज की हालत बिगड़ जाना आम बात है। कई बार तो यह लापरवाही मौत तक का कारण बन चुकी है। यह स्थिति केवल छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी प्रिस्क्रिप्शन का यह संकट मौजूद है। लिहाजा हाईकोर्ट का हस्तक्षेप एक जीवन रक्षक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। यह विषय केवल चिकित्सकीय नहीं बल्कि सामाजिक भी है।

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अक्सर मरीज कम पढ़े-लिखे होते हैं। जब वे डॉक्टर की पर्ची लेकर दवा की दुकान पर पहुंचते हैं तो उनकी समझ से बाहर होता है कि कौन-सी दवा कितनी बार लेनी है। कई बार दवा विक्रेता भी लिखावट को गलत समझ लेता है। इससे मरीज गलत समय पर दवा खा लेता है, डोज बिगड़ जाती है और बीमारी बढ़ जाती है। यह समस्या गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग मरीजों में और भी गंभीर हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालत ने सही कहा कि मरीज को अपनी बीमारी और इलाज की जानकारी मिलना उसका मौलिक अधिकार है। यदि प्रिस्क्रिप्शन ही अस्पष्ट और अधूरी जानकारी वाला हो तो यह अधिकार स्वतः ही बाधित होता है। इस संदर्भ में यह आदेश केवल चिकित्सा पद्धति के तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब तक देशभर में ई-प्रिस्क्रिप्शन (कंप्यूटर से बनी पर्ची) की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखें। यह सुझाव व्यावहारिक भी है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। डिजिटल हेल्थ रिकार्ड और ई-प्रिस्क्रिप्शन के कई लाभ हैं मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास सुरक्षित रहता है, फार्मासिस्ट को गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती, दवा कंपनियों और हेल्थ ईंश्योरेंस तक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और मरीज चाहे गांव का हो या महानगर का, उसे स्पष्ट जानकारी मिलती है। हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ-सुथरी लिखावट और स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन की ट्रेनिंग दी जाए। यदि मेडिकल शिक्षा के शुरुआती दौर से ही छात्रों को साफ लिखने और स्पष्ट पर्चा देने की आदत डाल दी जाए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या स्वतः ही खत्म हो सकती है। यह सुधार मेडिकल एथिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नीति बनाने का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत छोटे क्लिनिक और ग्रामीण डॉक्टरों को कंप्यूटर आधारित प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाए और स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि डॉक्टर पर्चे पढ़ने योग्य लिख रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की स्पष्टता स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार लाती है। पश्चिमी देशों में डॉक्टरों द्वारा हाथ से लिखे पर्चे अब लगभग अतीत की बात हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान में ज्यादातर अस्पतालों और क्लिनिकों में ई-प्रिस्क्रिप्शन ही मानक बन चुका है। भारत में भी 'डिजिटल इंडिया मिशन' और 'आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन' के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश इन पहलू को और गति देगा। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट को कमी से डिजिटल व्यवस्था लागू करना कठिन होगा। छोटे क्लिनिकों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर की लागत बड़ी बाधा है। डॉक्टरों पर पहले से ही प्रशासनिक बोझ है, ऐसे में अतिरिक्त प्रशिक्षण और औपचारिकताएं असुविधा पैदा कर सकती हैं। यह भी सही है कि मरीजों की भाषा और समझ अलग-अलग होती है। अतः केवल अंग्रेजी या कैपिटल लेटर्स काफी नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय भाषा में भी स्पष्टता जरूरी है। डॉक्टरों की लिखावट अब केवल भ्रजाक या व्यंग्य का विषय नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे-सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।

तृप्त ओशो

याद घर बुलाने लगी! इन थोड़े-से शब्दों में सारे धर्म का सार है--याद घर बुलाने लगी। जहां हम हैं, वहां हम तृप्त नहीं। जो हम हैं उससे हम तृप्त नहीं। एक बात निश्चित है कि हम अपने घर नहीं, परदेश में हैं। कहीं अजनबी की भांति भटक गए हैं। कहां जाना है यह भला पता न हो, लेकिन इतना मानो को पता है कि जहां हम हैं, वहां नहीं होना चाहिए। एक बेचैनी है। कुछ भी करो, कितना ही धन कमाओ, कितनी ही पद-प्रतिष्ठा जुटाओ, कुछ कमी है, जो मिटती नहीं। कोई घाव है, जो भरता नहीं। कोई पुकार है जो भीतर कहे ही चली जाती है: यह भी नहीं, यह भी नहीं; कहीं और चलो। खोजो घर। द्वार-द्वार दरवाजे-दरवाजे दस्तक दिए। न मालूम कितने- कितने जन्मों में, कितने-कितने ढंग से अपने घर को खोजा है। मगर सारी खोज एक ही बात की है कि कोई ऐसा स्थान हो, जहां तृप्ति हो। कोई ऐसी भावदशा हो, जिसमें कोई वासना न उठती हो। वासना का अर्थ ही है कि जो हम हैं, उसमें रस नहीं आ रहा, कुछ और होना चाहिए। चाह का अर्थ ही है बेचैनी। चाह उठती ही बेचैनी से। कोई अतृप्ति यत्र तत्रफ से घेरे है। यत्र मिल जाता है। फिर भी अतृप्ति वैसी की वैसी बनी रहती है-अछूती, अस्पर्शित। धर्म का जन्म मनुष्य के भीतर इस महत घटना से होता है-बेचैनी की इस घटना से। जहां है वहां हैं। जैसे परदेश में हैं, जहां न कोई अपनी भाषा समझाता, न कोई अपना है। जहां यत्र संबंध मन के मनाये हुए हैं; वास्तविक नहीं। और जहां पानी का धोखा तो बहुत मिलता है, पानी नहीं मिलता--मृग-मरीचिका है। दूर से दिखाई पड़ता जल का स्रोत, पास आते रेत ही रेत रह जाती है। इस भटकाव को हम कहते हैं संसार। इस भटकाव में घर की याद आने लगी तो धर्म की शुरुआत हुई।

पानी पर तिरता है आईना
आंख झिलमिलाने लगी

अगर बाहर देख-देखकर ऊब पैदा हो गई हो, देख-देखकर देख लिया हो, कुछ देखने जैसा नहीं है, आंख झपकने लगी हो, भीतर देखने का खयाल उठने लगा हो, आंख बंद करके देखने का भाव जगने लगा हो तो हो गई शुरुआत। हाथ भरके देख लिए, जब पाया तब राख से भरे पाया। कभी हीरों से भरा लेकिन हीरे राख हो गए। सोने से भरा, सोना मिट्टी हो गया। संबंधों से भरा, तथाकथित प्रेम से भरा और यब अंततः मूल्यहीन सिद्ध हुआ।

रीडर्स मेल

जागरूक बनें आमजन

भले ही हमारा देश आधुनिक और तकनिकी युग में सफर कर रहा परंतु अंधविश्वास की कु-नजर आज भी कहीं न कहीं हावी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चार बच्चों के साथ सो रहे दंपति को सांप ने डस लिया। अस्पताल ले जाने की बजाय पड़ोसियों ने झाड़ फूंक में ही समय गंवा दिया और जिसमे पति-पत्नी की मौत हो गई। अक्सर अंधविश्वास की वजह से लोगों की जीवन लीला समाप्त होती है, जबकि अब देश में सर्प दंश का आसानी से उपचार संभव है। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। सबक यही होना चाहिए कि सतर्कता और सूझबूझ से हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, न कि झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास के भरोसे रहना चाहिए। समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं और डॉक्टरी पेशे में हैं, उन्हें भी इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र

सोशल मीडिया पर कम वक्त दें

सोशल मीडिया ने हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा घेर लिया है इससे जीवंत संवाद सिकुड़ता जा रहा है। आज अधिकांश लोग दिन की शुरुआत से लेकर रात तक मोबाइल स्क्रीन पर ही उलझे रहते हैं। एक ओर यह हमें सूचनाएं, सुविधा और वैश्विक संपर्क देता है वहीं यह मानवीय रिश्तों में दूरी भी पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जितना अधिक समय बिताते हैं उतना ही वे वास्तविक संवाद और व्यक्तिगत मुलाकातों से दूर होते जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सेवाओं ने सुविधा तो दी है, लेकिन इसके कारण बाजार, पड़ोस और समाज से मिलने-जुलने के मौके कम हुए हैं। इस कमी से धीरे-धीरे अकेलेपन की भावना गहराने लगती है। मानवीय संबंध जब केवल आभासी और संवाद में पसंद तक सीमित हो जाते हैं तब आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से सामाजिक विखराव और मानसिक थकान बढ़ रही है।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

एकजुटता ही तरक्की की राह

भारत और चीन के रिश्ते पूरे एशिया की शांति और प्रगति को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद और अविश्वास ने इन संबंधों को काफी हद तक कमजोर किया, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात और यह संदेश कि वे 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार' हैं, न केवल सुकून भरा है बल्कि भविष्य की संभावनाओं से भी भरपूर है। सीमा पर शांति बनाए रखने, सीमा व्यापार को फिर से खोलने और कैलाश-मानसरोवर यात्रा जैसे सांस्कृतिक धार्मिक आदान-प्रदान को शुरू करने के प्रयास यह दिखाते हैं कि दोनों देशों ने समझ लिया है कि तनाव किसी के हित में नहीं है। आपसी संवाद और विश्वास बहाली के ये कदम निश्चित रूप से एशिया में स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम हैं। फिर भी यह जरूरी है कि ये वादे केवल कागजों और सम्मेलनों तक सीमित न रहें। सीमा विवाद का स्थायी समाधान, व्यापार संतुलन और नागरिकों के बीच सहज संपर्क ही असली कसौटी होंगे। यदि भारत और चीन मतभेदों को छोड़कर सहयोग की राह पर आगे बढ़ें, तो यह न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक सकारात्मक उदाहरण होगा।

आराध्या सिंह, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

लिखावट पर अदालत की फटकार

महारा पुष्टिदया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिला कलक्टर द्वारा लखनऊ प्रेस्टिज नाल कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2.3, 4 सेक्टर-11, नोएडा से मुद्रित तथा तथा 1200-1210, आकाश लाल, नवकार काउन्स, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। ‘ज्ञानीय संपादक - रत्नेश सिंहा’ ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444722, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-35, अंक 10
आर.एन.आई. न. 23460/01, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
"इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी जवाबदेही के लिए उत्तरदायी

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 02-09-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: dilip.lal Time: 09-01-2025 21:23 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 2 सितंबर 2025

प्लीज टेक केयर SIR

बिहार में चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया लगातार चर्चा में है। जहां एक तरफ इसे लेकर शुरू की गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव को वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में विपक्षी नेताओं की रैली के साथ समाप्त हुई, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर नए आदेश जारी किए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह पूरा प्रकरण आखिरकार कैसा मोड़ लेगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर किस तरह का असर डालेगा।

AI Image

आरोप-प्रत्यारोप जारी

विपक्षी नेताओं की रैली। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली में विपक्षी नेताओं ने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई इस प्रक्रिया के औचित्य को लेकर वे अभी आश्वस्त नहीं हैं। इस रैली में भी राहुल गांधी समेत तमाम वक्ताओं ने कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग को आरोपों के दायरे में शामिल रखा। इससे यह साफ हो गया है कि अगर विपक्षी नेताओं को भरोसे में लेने की कोई कारगर पहल चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से नहीं होगी, तो यह मुद्दा उठता रहेगा।

कोर्ट में सुनवाई । सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का जहां तक सवाल है तो वहां भी विपक्षी दल और चुनाव आयोग एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगाते नजर आए। जहां विपक्षी दलों के वकील इस प्रक्रिया की खामियों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाते रहे, वहीं चुनाव आयोग के वकील ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या इस प्रक्रिया में नहीं, बल्कि माइंडसेट में है। उनके मुताबिक दूसरे पक्ष की मानसिकता ही खोट निकालने की हो गई है।

भरोसे की कमी । सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि असल सवाल भरोसे की कमी का है। संभवतः देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग जैसी एक संवैधानिक संस्था इस तरह से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है दोनों पक्षों का एक-दूसरे पर अविश्वास ही विवाद की जड़ है। इसीलिए शीर्ष अदालत ने बिहार विधि सेवा अधिकारियों से पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने को कहा है। ये वोटरों और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन शिकायत करने में मदद करेंगे और अपनी गोपनीय रिपोर्ट जिला जजों को सौंपेंगे, जिन पर आगे विचार किया जाएगा।

आगे की राह । इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यथासंभव उपयुक्त ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में सभी पक्षों का विश्वास जीतने और सभी योग्य मतदाताओं की आशंकाएं दूर करने में किस हद तक कामयाब हो पाता है।

धूप-छांव

एक नन्ही सी छुवन

प्रणव प्रियदर्शी

हल्का सा स्पर्श जो काम करता है, वह पकड़ना, धक्का देना या झिंझोड़ा जाना भी नहीं करता। यह बात जिंदगी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। इसलिए वह हमें झिंझोड़ना और झकझोरना बंद नहीं करती, लेकिन बीच-बीच में एकाध अनुभव उस मामूली से स्पर्श का भी दे देती है या किसी किरदार के जरिए दिलवा देती है। उस स्पर्श की महिमा कहिए कि वह पल जो कायदे से दर्ज भी नहीं होना चाहिए था, जिंदगी भर आपके साथ बना रह जाता है।

वाकया गुजरात के एक छोटे से शहर वापी का है। वहां तीसरी या चौथी कक्षा में एक लड़के का एडमिशन हुआ। स्कूल नया था, परिवेश अनजाना। कुछ ऐसा हुआ कि क्लास के एक लड़के की गेंद कहीं खो गई। गेंद नहीं मिली तो हवा में यह आरोप उछला कि उसकी गेंद चोरी हो गई और शक के घेरे में आया वह नया लड़का। इस बेचारे की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और क्यों उस पर चोरी का आरोप लग गया। उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि किससे और कैसे सफाई दे। लंच टाइम में शर्म, बेबसी और अपमानबोध से भरा अकेला रोता हुआ कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी उसके कानों में आवाज आई, अंदर स्टाफ रूम में दो टीचर बात कर रहे थे, 'अरे वह नया बच्चा? नहीं-नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी, वह चोरी कर ही नहीं सकता।' बाद में गेंद भी मिल गई, क्लासटीचर ने पूरी क्लास को डांटा भी कि ऐसे निराधार आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बच्चे के दिलोदिमाग पर सबसे ज्यादा असर हुआ उस अनजान आवाज का, जिसने बिना किसी पूछताछ के उसमें सौ फीसदी यकीन जताया था।

ऐसे ही यारी, दोस्ती और अफेयर के तमाम किस्सों-अनुभवों पर भारी पड़ती है, कुछ मिनट की वह बातचीत जिसमें तारीफ भरी नजरों का स्पर्श भर हुआ। एक ने दूसरे से कहा, 'आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए।' 'क्यों?' 'आई डोंट लाइक इट।' 'बट इट्स योर प्रॉब्लम'/ 'आइ नो'। बस्स, चेहरे पर आया हलकी सी बेबसी का वह भाव जहन पर ऐसा छपा कि फिर मिटा ही नहीं। फिर कोई मुलाकात, कोई संपर्क नहीं, लेकिन वह पल इसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। शायद इन्हीं पलों के मद्देनजर किसी कवि ने लिखा है, 'एक नन्ही सी छुवन की नाव खेकर, मैं समंदर पार जाना चाहता हूं।'

बोल वचन

अंग्रेजी में का बा

राहुल पाण्डेय

कुछ साल पहले एक रैप सॉन्ग काफी हिट हुआ था। इस गीत का मुखड़ा था- बंबई में का बा? बाद में इसी तर्ज पर राजनीतिक गाने भी बने, जिसमें कभी पूछा जाता कि यूपी में का बा, तो कभी बिहार में का बा? इसमें आया बा शब्द अवध से लेकर भोजपुर तक बहुतायत में प्रयोग होता है। अवधी और भोजपुरी में इस शब्द का अर्थ 'है' होता है। यानी बंबई में का बा का अर्थ है, बंबई में क्या है? लेकिन 'है' के अर्थ से पहले अधिकतर लोग इसमें मां जैसी इज्जत का अर्थ पाते हैं। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा तो बहुत बाद में जुड़ा, उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ यह इज्जत पहले ही जुड़ चुकी थी। बल्कि कस्तूरबा की माताजी के साथ भी, जिनका नाम था व्रजकुंवरबा। गुजराती में स्त्रियों के सम्मान के लिए उनके नाम के साथ बा शब्द जोड़ा जाता है। मालवी गुजराती की थोड़ी नजदीकी है तो वहां भी इस शब्द को नाम के साथ इज्जत देने के लिए जोड़ते हैं। लेकिन बा का स्रोत अगर संस्कृत है तो इसका अर्थ जल भी होता है। कन्नौजी में इसे 'उस' के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। गढ़वाली में पिता के लिए, बुंदेली में 'वह' के लिए, तो मैथिली में अथवा के लिए या का प्रयोग होता है। जाहिर है, बा के इतने अर्थों को किसी एक शब्द में समेट पाने में इंग्लिश अभी तक अक्षम ही रही है। इसलिए कोई यह भी पूछ सकता है, अंग्रेजी में का बा?

AI Image

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मोदी के लिए अच्छा माहौल तो बनाया, लेकिन ठोस ऐलान से बचे

क्या दोस्ती का यह डांस मुमकिन है?

रंजीत कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की चीन के थ्येनचिन शहर में शांघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन इसमें चीन के शीर्ष नेता की ओर से आपसी तनाव दूर करने के लिए किसी ठोस जमीनी कदम का जिक्र नहीं किया गया।

यात्रा की भूमिका । मोदी और शी के बीच इस बैठक की जमीन पिछले महीने की 18 तारीख को तैयार हुई थी, जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे। तब आपसी रिश्तों में बेहतरी के लिए 10 सूत्रीय सहमति बनी थी। इनमें बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के साथ आपसी भरोसा पैदा करने की बात शामिल थी। साथ ही, कुछ साझा सैन्य और विशेषज्ञ दलों के गठन की बात भी कही गई थी।

आशा पूरी नहीं। भारत को आशा थी कि थ्येनचिन में शी लद्दाख सीमा पर 50 हजार से अधिक फौज को पीछे ले जाने या पूरी तरह से हटाने के बारे में कोई ऐलान करेंगे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से तनाव बना हुआ है। भारतीय पक्ष इस बात पर जोर देता रहा है कि लद्दाख सीमा पर अप्रैल, 2020 जैसी स्थिति को पूरी तरह बहाल किया जाए, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी है।

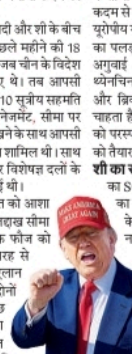

भारत पर नजर । इसलिए चीन के राष्ट्रपति की ये बातें खोखली लगती हैं कि ड्रैगन और हाथी को डांस करना चाहिए या भारत और चीन के सामने ऐतिहासिक जिम्मेदारियां हैं। आज भारत किस तरफ झुकता है, इस पर दुनिया की नजर है। मोदी के ताजा चीन दौरे के बाद भारत के अगले कदम से तय होगा कि अमेरिकी नेतृत्व वाले यूरोपीय गठजोड़ और चार देशों वाले क्वॉड का पलड़ा भारी होता है या चीन-रूस की अगुवाई वाले SCO और ब्रिक्स का। थ्येनचिन में लगा कि चीन, भारत को SCO और ब्रिक्स के भविष्य के साथ जोड़ना चाहता है। इसके लिए वह द्विपक्षीय रिश्तों को परस्पर लाभ के संबंध की ओर ले जाने को तैयार है।

शी का संदेश। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी का SCO बैठक के लिए थ्येनचिन जाने का जब कार्यक्रम बना था, तब भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में तल्खी नहीं आई थी। ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बात बिगड़ी है। इसलिए मोदी के चीन दौरे की सामरिक पर्यवेक्षकों के बीच अहमियत बढ़ गई। हालांकि, मोदी के इस दौरे को राष्ट्रपति शी ने खुशनुमा बनाने की कोशिश की। इसे उनकी ओर से भारत के लिए सामरिक संदेश भी कहा जा सकता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए ब्रिक्स-SCO के पलड़े पर वह पांव रख दे तो इससे इन संगठनों का वजन बढ़ेगा। लेकिन यह तभी मुमकिन है, जब भारत और चीन के रिश्ते सामान्य हों।

रिश्ते की डोर
- शी चाहते हैं, SCO-ब्रिक्स में सक्रिय हो भारत
- क्वॉड को लेकर भारतीय रुख पर सबकी नजरें
- चीन-भारत के बीच कई मुद्दों को लेकर है विवाद

भारत से जुड़े सवाल। उधर, ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उससे दोनों देशों की सामरिक साझेदारी पर आंच पड़ी है। इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला तो यही है कि क्या भारत अमेरिका व क्वॉड से दूरी बनाने जा रहा है? दूसरा सवाल यह है कि क्या चीन और रूस, भारत की इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरा यह है कि भारत को क्या चीन अपने पाले में लाने के लिए उसकी सामरिक चिंताएं दूर करेगा? क्या वह आतंकवाद, सुरक्षा परिषद और NSG (48 देशों के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) की सदस्यता के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देगा?

क्या प्रेशर डालेगा चीन । कुछ और प्रश्न भी हैं, जैसे- क्या चीन बेल्ट एंड रोड की विश्वव्यापी योजना में साथ देने का भारत पर दबाव डालेगा? क्या वह भारत से कहेगा कि ताइवान के साथ अपने रिश्ते तोड़े और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को राजनीतिक प्रोत्साहन देना बंद करे। क्या वह सीमा मसले के हल के लिए भारत से अक्साई चिन को चीन का हिस्सा मानने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले चीनी राजमार्ग (CPEC) का विरोध नहीं करने को कहेगा? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है।

चीन की चाहत। वहीं, शी की हसरत होगी कि भारत अपने यहां चीनी निवेश की खुली छूट दे। वह टिकटॉक और 50 से अधिक ऐप्स पर लगी पाबंदी हटाए। अगर भारत इन मांगों को मान ले तो हो सकता है कि चीन, भारत के साथ सीमा विवाद को सैद्धांतिक तौर पर हल करने को तैयार हो जाए और तवांग सहित अरुणाचल प्रदेश के इलाके पर दावा छोड़कर भारत के साथ समग्रता में सीमा समझौता करने को तैयार हो जाए। बदले में वह अपने यहां भारतीय माल को बेहतर एक्सेस के लिए तैयार हो सकता है ताकि व्यापार असंतुलन दूर हो।

साथ ही, वह भारत से यूरिया, मैनेटज और दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर पाबंदी हटा ले। चीन की समझाना होगा कि ड्रैगन व हाथी का नृत्य दबाव व चिंता रहित दोस्ती की ठोस जमीन पर ही मुमकिन है।

(लेखक विदेश और सामरिक मामलों के जानकार हैं)

जब शांतिदूत चचा ने सुनाया दर्द भरा अफ़साना

आलोक सिंह भदौरिया

मैं पार्क का आखिरी चक्कर लगाकर सुस्ताने के लिए बेंच पर बैठ गया। आंखें बंद करके गहरी सांसें ले ही रहा था कि लगा बगल में कोई आकर पसर गया है। मैंने धीमे से आंख खोलकर देखा तो पाया कि सूट-बूट पहने, गले में लाल टाई, उससे ज्यादा लाल-लाल आंखों वाले एक बुजुर्ग बैठे हैं। शक्ल सात समंदर पार वाली लेकिन गालियां एकदम खालिस हिंदुस्तानी।

बेगैरत, अहसान फरमोश, इंसानियत नाम की चीज नहीं..। मैंने पूछा क्या हुआ सर, उन्होंने खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। बोले, जब एलियन अटैक हुआ तो दुनिया को किसने बचाया, हमने। जब गॉडजिला का आतंक पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था तो अपनी परवाह न करते हुए हम अपनी जान पर खेल गए। जब मशीनों ने पूरी इंसानियत को खत्म करने की ठानी तो सारे देश कहां थे, तब हमी ने उनका आखिरी सांस तक मुकाबला किया और जीत हासिल की। अब... अब हमीं को भूल गए।

मैं कुछ समझा नहीं, बस डर के मारे केवल जी-जी कहा। लेकिन वह समझ गए। मुझसे बोले, न्यूज नहीं देखते क्या? फिर जेब से मोबाइल निकालकर एक-एक वाकये की फोटो दिखाने लगे। मैं अवाक रह गया, ये तो तमाम हॉलिवुड फिल्मों के पोस्टर और उनकी क्लिपें हैं। मैं हिम्मत करके बोला, ये तो शायद फिल्में हैं। वह गुर्रा कर बोले, 'फिल्में हैं? मिस्टर ये सबूत हैं, मैं जेब में लेकर पूरी दुनिया को दिखाता घूम रहा हूं। दिमाग खराब हो गया है आपका।' मैंने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है। लेकिन यह तो बता दीजिए कि अब क्या हो गया।

AI Image

ऐवें कुछ भी

उन्होंने ऐसी नजरों से देखा जैसे मुझे साबुत निगलना चाहते हों। गरजकर बोले, 'आपस में लड़ते हो, फिर कहते हो कि लड़ाई खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई लड़ाई? बिना हारे आगे कैसे खत्म हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बगैर लड़ाई खत्म करने की?'

इतने में दो बालक गेंद तड़ी खेलते हुए हमारे पास आए। एक ने दूसरे की तशरीफ पर प्लास्टिक की गेंद दे मारी, दूसरे ने फौरन गेंद लपक ली। पलटवार के लिए जैसे ही हाथ उठाया, विदेशी चचा ने उसकी कलाई पकड़ ली। चिल्ला के बोले, 'तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते लड़ाई करने की। ये सब मेरे काम हैं।' दोनों लड़के डर गए, रोने लगे। बोले, 'अंकल हम तो केवल खेल रहे थे। लड़ाई-वड़ाई कुछ नहीं हुई।' चचा और जो से बमक उठे और बोले, 'कैसे नहीं हुई? हमने अपनी आंखों से देखा, हमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा वरना इस युद्ध में करोड़ों जाने चली जातीं।'

बच्चे वाकई सहम गए। विदेशी चचा ने प्लास्टिक की बॉल अपनी जेब में रखते हुए कहा, 'शाम को ठीक सात बजे पार्क के बीचों बीच अपने-अपने परिवारों को लेकर आना। हमारा सम्मान समारोह है। इस भयानक युद्ध को रुकवाने के लिए हमें सदी के महानतम शांति दूत का पुरस्कार दिया जाना है। और सुनो... अगर नहीं आए तो दोनों के परिवारों की खैर नहीं।' अचानक जोरदार धमाकों की आवाज आई, हमने आंखें मलीं तो पाया कि हमें सोफे पर नींद आ गई थी। हमारे सपूत मोबाइल पर हॉलिवुड मूवी देख रहे थे। हमने उनके हाथ से फोन झटक कर कहा, बेटा कुछ हिस्ट्री, जॉग्रफी भी पढ़ लिया करो वरना विदेशी चचा जैसे हो जाओगे।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

योग है आध्यात्मिक शक्तियों को जगाते रहने की विधा

स्वामी अवधेशानंद गिरि

योग ऐसी साधना है, जो मनुष्य को बौद्धिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ-साथ उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण कला है। योग से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, इसलिए इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाकर जीवन को आनंद से भरा जा सकता है। योग में कार्यक्षमता बढ़ाने की क्षमता है, इसलिए इसका महत्व हर जगह देखा जा रहा है।

योग शरीर और आत्मा का मिलन कराता है। अक्सर लोग इसे मात्र व्यायाम मानते हैं, लेकिन यह एक संपूर्ण दर्शनशास्त्र है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह भारतीय संस्कृति की अमूल्य विद्या है, जिसे अपनाने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और व्यावहारिक विकास होता है। योग से जीवन दिव्य बनता है और व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने में समर्थ होता है।

जीवन की परिपूर्णता, समाधान और मनुष्य में निहित आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण की वैज्ञानिक विधा है योग। यह आनंद का ऐसा स्रोत है, जो मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग के नियमित अभ्यास से आचार-विचार अच्छे होते हैं और जीवन में अनुशासन आता है। यही कारण है कि भारत ने योग और अध्यात्म विश्व को उपहार में दिया, जिसके महत्व को पूरी दुनिया समझती है।

चरित्र निर्माण में भी योग का बहुत महत्व है। इससे चेहरे पर तेज और वाणी में मधुरता आती है। यह तनावमुक्त जीवन देता है। परिवार और समाज में मधुर संबंध स्थापित करने में भी योग सहायक होता है। आगे बढ़कर यही देश के विकास में योगदान देता है। योग नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, जिससे व्यक्ति निराशा और हताशा से मुक्त होकर उत्साहपूर्ण जीवन जी पाता है।

योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों की साधना है। योग किसी विशेष साधन का मोहताज नहीं है। इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। नियमित आसन और प्राणायाम भी हमें निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं। यम-नियमों के पालन से जीवन अनुशासित बनता है, ध्यान और धारणा से तनाव दूर होता है तथा कार्यक्षमता बढ़ती है।

ऋषि-मुनियों ने योग को मानव जीवन का अभिन्न अंग बताया है। यह न केवल स्वास्थ्य की कुंजी है, बल्कि आत्म-साक्षात्कार का मार्ग भी है। योग हमें सिखाता है कि मन को संयमित किए बिना साधना अधूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और दिव्य बनाने की कला है।

प्रस्तुति : सुभाष चन्द्र शर्मा

SSC एग्जाम में कई बदलाव किए गए हैं, जिनसे कैंडिडेट्स की शिकायतें दूर होंगी

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट गुस्से में हैं। वे इसमें रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। आयोग ने भी माना है कि परीक्षा में सुधार की जरूरत है। अब आने वाली परीक्षाओं में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, इन सब महत्वपूर्ण सवालों पर आयोग के चेयरमैन **एस गोपालाकृष्णन** ने NBT के **भूपेंद्र शर्मा** से विस्तार से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अहम अंश:

■ एग्जाम सिस्टम में क्या बड़े बदलाव किए गए?

नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म्युला बदला। 2013 से SSC सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में करा रहा है। छह साल तक नॉर्मलाइजेशन का दूसरा फॉर्म्युला था, जिसे अब बदला गया है। पुराने फॉर्म्युले में कोई कमी थी, यह तो नहीं कहूंगा। वहीं, नॉर्मलाजेशन भी कई तरह से कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की सबसे बड़ी शिकायत थी कि एग्जाम अगर 10, 20, 40 शिफ्ट में हो रहे हों तो हो सकता है कि एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान हो, दूसरा मुश्किल। अब SSC ने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन आपकी ही शिफ्ट में होगा। माना लीजिए सुबह वाला एग्जाम आसान रहा, शाम वाली शिफ्ट का एग्जाम मुश्किल रहा, दोनों एग्जाम में 10-10 हजार कैंडिडेट्स बैठे तो नॉर्मलाइजेशन एक-एक शिफ्ट में होगा। पर्सेंटाइल के हिसाब से अगर हमें टॉप 5 पर्सेंट कैंडिडेट्स चाहिए तो सुबह की शिफ्ट के अंदर टॉप 5 पर्सेंट, दूसरी शिफ्ट में टॉप 5 पर्सेंट का चयन करेंगे।

■ क्या फाइनल परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाने की कोशिश होगी?

ज्यादा कैंडिडेट व सेंटर की कमी के कारण अभी तक हम मुख्य परीक्षा को दो या तीन शिफ्ट में करवाते हैं। अब तय किया है और अदालत का भी आदेश है, ऐसी परीक्षा को दो-तीन शिफ्ट में करवाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए तकनीक की मदद लेकर मुख्य परीक्षा को एक शिफ्ट में करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं।

■ कहा जाता है कि एक ही एजेंसी पर अधिक काम का दबाव डाल दिया गया...

इस बार नई एजेंसी को सेंटर तलाशने में दिक्कत हुई, जिसके चलते कैंडिडेट्स को दूर-दूर सेंटर मिले, लेकिन अब प्लैटफॉर्म व टेक्नॉलजी सॉल्यूशन के जरिए इस समस्या को हल किया जा रहा है। नए वेंडर का काम सेंटर पर एग्जाम करवाना है, सिक्युरिटी किसी और एजेंसी के जिम्मे होगी, ऐप्लिकेशन मैनेजमेंट तीसरी एजेंसी का होगा और कंटेंट यानी क्वेश्चन पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी किसी ओर की होगी। साथ ही, SSC क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर नजर रखेगा। इन चारों के तालमेल से एग्जाम होंगे।

■ आधार से ऑथेंटिकेशन को लेकर कैंडिडेट्स को काफी समस्याएं आई हैं...

SSC एग्जाम में malpractice यानी परीक्षा में नकल, किसी और की जगह एग्जाम देना जैसी समस्याएं हैं। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार से ऑथेंटिकेट करने का नियम लागू हुआ है, जो परीक्षा देने से लेकर नौकरी जॉइन करने तक रहेगा।

■ एग्जाम में सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?

सिक्युरिटी के लिए सिस्टम्स की निगरानी के लिए नई टेक्नॉलजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले एग्जाम में जो समस्याएं आई हैं, उनमें से ज्यादातर कुछ जगहों पर कंप्यूटर पुराने होने, नेटवर्क ठीक न होने जैसी थीं। अब हम अपनी एप्लिकेशन को सपोर्ट करके, उसी तरह का हार्डवेयर लगाकर बेहतर सेंटर को चुन रहे हैं। और कैंडिडेट्स की समस्याओं का हल कर रहे हैं।

■ क्या पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम की कोई प्लानिंग है?

SSC में कैंडिडेट्स की संख्या काफी अधिक होती है। इसलिए एग्जाम कई शिफ्ट में करने पड़ते हैं। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ट फॉर्मेट है। हमारा पेन एंड पेपर मोड में परीक्षा करवाने का इरादा नहीं है। इससे सभी को दिक्कत होगी। कैंडिडेट्स की भी परेशानी बढ़ेगी। क्वेश्चन पेपर लीक होने की आशंका बढ़ेगी, साथ ही एग्जाम में गड़बड़ी का रिस्क भी बढ़ेगा। वहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से सुरक्षित तरीके से परीक्षा करवाई जा सकती है। रिजल्ट भी इससे जल्दी देने में आसानी होती है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ नए रास्ते निकलें

1 सितंबर का संपादकीय 'राइट ट्रैक पर रिश्ते' पढ़ा। स्पष्ट है कि गलवान घाटी की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चीन गए हैं। उन्होंने वहां एससीओ (SCO) की बैठक में हिस्सा लिया और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से द्विपक्षीय वार्ता भी की। चीन आज दोस्ती का दावा कर रहा है, लेकिन वह गलवान में देख चुका है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत ने दृढ़ इच्छाशक्ति और ताकत दोनों का प्रदर्शन किया है। टैरिफ विवाद के बाद दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब आना पड़ा। हालांकि बीते कई वर्षों से धीरे-धीरे आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिशें चल रही थीं, मगर इस बार परिस्थितियां और समय का तकाजा दोनों ही इस मुलाकात को अनिवार्य बना रहे हैं। फिर भी भारत को विशेष सतर्कता बरतनी होगी ताकि दोस्ती के नए रास्ते निकल सके।

इंद्र सिंह धिगान, नई दिल्ली

■ अमेरिका का दबाव

यह पत्र 29 अगस्त के संपादकीय 'वार्ता से रास्ता निकले' से संबंधित है। अमेरिकी वित्त मंत्री का बयान निसंदेह सकारात्मक है, लेकिन उन्हें अपने राष्ट्रपति को भी यह समझाने की जरूरत है कि भड़काने वाले बेतुके भाषण देना और भारत पर फिजूल का दबाव डालना बंद करें। रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारत का कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक द्विपक्षीय व्यापार का प्रश्न है, तो भारत को यह समझ लेना चाहिए कि चीन हमारा व्यापार पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन दोस्त नहीं। मौजूदा हालात में भारत को यूरोपीय संघ के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौता करना चाहिए।

बाल गोविंद, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ भेज करें।

अंतिम पत्र

शी ने मोदी से कहा, अब दोस्ती ही विकल्प - एक खबर
- अब चीन को दोस्ती का मतलब समझ आया!

प्रतिभा गुप्ता

आर.एन.आई. नं. 210/57 के अधीनस्थ मुद्रित। टिबिया आधुनिक के लिए संपादक आशीष मुखोपाध्याय द्वारा, डीडीए/ए-7 सफदरजंग एंक्लेव, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के लिए राकेश कुमार द्वारा, 7 सफदरजंग मार्ग, नई दिल्ली-110003 पेजमेकर द्वारा एडवांस ग्राफिक्स प्रा. लि., प्लॉट 12, ईपीआईपी, इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार, उत्तराखंड में मुद्रित। फोन: 011-23368300, फैक्स: 23368300, ई-मेल: 22-01-2017, संपादक-स्वामित्व: सुप्रभा सिंह द्वारा, दिल्ली-110002 टीवीएन के लिए मुद्रक: एन. सीतारमन, टेक्नो मुद्रक प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित। प्रकाशन केंद्र: दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, रांची, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, देहरादून, गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोयंबटूर, मंगलूरु, मैसूरु, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, वारंगल, तिरुपति, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रायपुर, जम्मू, श्रीनगर, शिमला, धर्मशाला, इंदौर, नागपुर, गोवा, कोलंबो, काठमांडू, ढाका, दुबई, अबू धाबी, शारजाह, सिंगापुर, कुआलालंपुर, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, ऑकलैंड, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजिलिस, शिकागो, डैलस, टोरंटो, वैंकूवर, लंदन, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, बर्मिंघम, एडिनबर्ग, ग्लास्गो, फ्रैंकफुर्ट, पेरिस, मिलान, रोम, मैड्रिड, बार्सिलोना, एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स, ज्यूरिख

जब आपका विरोधी गलती कर रहा हो, तो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। -नेपोलियन बोनापार्ट

तियानजिन घोषणा में चीन समेत सभी देशों द्वारा 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करना, भारत के लिए यकीनन एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी तो है ही, इससे वैश्विक कूटनीति में भारत की दमदार उपस्थिति भी रेखांकित होती है।

कूटनीतिक कामयाबी

जून में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद साझा पोषणपत्र पर हस्ताक्षर से भारत के इन्कार के दो महीने बाद एससीओ शिखर सम्मेलन की तियानजिन घोषणा में पाकिस्तान और चीन समेत सभी देशों द्वारा 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करना, भारत के लिए यकीनन एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी तो है ही, इससे वैश्विक कूटनीति में भारत की दमदार उपस्थिति भी रेखांकित होती है। शिखर सम्मेलन में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की नीति को सुरक्षा, संपर्क और अवसर के तीन स्तंभों पर आधारित बताया। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर कि आतंकवाद मानवता के लिए एक साझा चुनौती है और इससे निपटने में किसी भी तरह का दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं हो सकता, जो संदेश दिया है, वह उन देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अक्सर सहयोग की भाषा बोलते हैं, पर व्यवहार में संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उनका यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि मजबूत संपर्क व्यापार के साथ विश्वास और विकास के द्वार भी खोलता है। बिना नाम लिए अमेरिका को भी संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि संप्रभुता की अनदेखी करने वाला संपर्क विश्वास और अर्थ खो देता है। जाहिर है कि यह त्रिआयामी दृष्टिकोण भारत की रणनीतिक सोच के साथ क्षेत्रीय व वैश्विक सहयोग को बढ़ाया देने में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को भी द्योतित करता है। एससीओ में भारत की भूमिका केवल औपचारिक सदस्यता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मंच उसके लिए मध्य एशिया से लेकर यूरेशिया तक नए कूटनीतिक और आर्थिक अवसरों का द्वार है। हालांकि, इससे जुड़ी भू-राजनीतिक चुनौतियों को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान से जटिल रिश्तों के बावजूद भारत का मजबूत रुख इन देशों के लिए भी एक संदेश है कि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए भी

संगठन के मूल उद्देश्यों-सहयोग और स्थिरता-को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जब दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय हो रही है और पश्चिमी शक्तियों का दबदबा धीरे-धीरे संतुलित हो रहा है, तब एससीओ जैसे मंच पर दो महाशक्तियों (रूस व चीन) के सामने भारत का सशक्त रुख वैश्विक व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और संतुलित बनाने की दिशा में भी योगदान देने वाला है। आतंकवाद पर कठोर रुख, सहयोग पर संतुलित नजरिया और विकास की साझा आकांक्षा, ये तीनों दर्शाते हैं कि वैश्विक भू-राजनीति चाहे कोई भी करवट ले, भारत को महज एक क्षेत्रीय शक्ति मानकर खारिज नहीं किया जा सकता।

हाथी, ड्रैगन और अमेरिका

ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद नई दिल्ली के पास दो ही विकल्प थे। पहला, अमेरिका के आगे झुक जाना और रूस से तेल खरीदना बंद कर देना। लेकिन इसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। दूसरा विकल्प था, मजबूती से डटे रहना और दूसरे अवसरों की तलाश करना। भारत ने यही विकल्प चुना है।

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा 50 फीसदी टैरिफ थोपे जाने के बाद भारत ने भी वही कदम उठाया, जो दुनिया के अन्य देशों ने उठाया, यानी चीन, रूस और अन्य ग्लोबल साउथ देशों के साथ नजदीकी बढ़ाई, ताकि तेजी से पक्षपातपूर्ण और विघातक होती स्थिति से निपटने के तरीके खोजे जा सकें। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने इसके लिए उचित मंच प्रदान किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा अन्य नेताओं से मुलाकात की, जो व्यापार को हथियार बनाने से परेशान हैं।

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद नई दिल्ली के पास दो ही विकल्प थे। पहला, अमेरिका के आगे झुक जाना और रूस से तेल खरीदना बंद कर देना। लेकिन इसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि रूस हमारा सदाबहार मित्र है और किसी के दबाव में आना मोदी की मजबूत छवि के अनुकूल नहीं है। दूसरा विकल्प था, मजबूती के साथ डटे रहें और दूसरे अवसरों की तलाश करें। लगता है कि फिलहाल भारत ने यही विकल्प चुना है। हालांकि, विदेश नीति विशेषज्ञों ने सलाह दी कि भारत को अल्पकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घावधि में यह अच्छा रहेगा। पिछले रविवार को मोदी-जी की मुलाकात के पीछे यही संदर्भ था। इसका तात्कालिक निष्कर्ष दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली और वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना था। यह एक नाटकीय बदलाव है।

अमेरिका ने निश्चित रूप से संभावित परिणाम का पूर्वानुमान लगाया होगा। मोदी-जी की मुलाकात को भारत की अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखने की नीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इससे दिल्ली के लिए और भी ज्यादा भू-राजनीतिक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। जाहिर है, ट्रंप इसे हल्के में नहीं लेंगे और संभव है कि भारत एवं रूस के खिलाफ और भी दंडात्मक कदम उठाएं, क्योंकि अमेरिका रूस द्वारा भारत को रियायती दरों पर तेल बेचने का विरोध करता है।

द *न्यूयॉर्क टाइम्स* के मुताबिक, इस वर्ष भारत की मेजबानी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में ट्रंप शामिल नहीं होंगे, जिसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अगर ट्रंप इसमें आते हैं और चीन के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो यह दिल्ली और बीजिंग के बीच नए सिरे से बने तालमेल के लिए परीक्षा जैसा होगा। फिलहाल, भारत को रूसी तेल खरीदने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।

हालांकि, कई अमेरिकियों ने यह महसूस किया है कि ट्रंप ने चीन को दंडित करने की कोशिश नहीं की है, जो भारत से अधिक तेल रूस से खरीदता है। चीन ने तो अमेरिका के विरुद्ध टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की, जबकि भारत ने समझौतावादी रवैया अपनाया, जिसे उसकी कमजोरी समझा गया। दरअसल, मोदी द्वारा भारत-पाकिस्तान विवाद को खत्म करने का श्रेय नहीं देने के कारण ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार यह दावा दोहराया है। अब पता चला है कि वह चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह भारत भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का समर्थन करे। लेकिन मोदी भारत के इस रुख का उल्लंघन नहीं कर सकते कि यह पाकिस्तान के साथ सुलझाया जाने वाला द्विपक्षीय मुद्दा है। भारत पाकिस्तानी आतंकी हमले के बदले में सौदेबाजी करते हुए नहीं दिख सकता। इसलिए, भारत-अमेरिका रिश्तों में वर्तमान जटिलता का एक व्यक्तिगत पहलू भी है।

हाल के महीनों में भारत और चीन के रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। एक साल पहले, भारत ने अपने व्यापारिक वर्ग के आग्रह पर चीन से रिश्ते में नरमी लाई। नतीजतन द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई और व्यापार घाटा 93 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि सीमा पर झड़पें हुईं और दोनों पड़ोसी राजनयिक मोर्चों पर एक-दूसरे के विरोधी हैं। इस साल मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संक्षिप्त सैन्य संघर्ष हुआ, तो उसमें परोक्ष रूप से चीन भी शामिल था। पाकिस्तानी सेना ने लड़ाकू विमानों और रडार प्रणालियों सहित चीन निर्मित उपकरणों का भारी इस्तेमाल किया। भारत ने चीन के खिलाफ कोई औपचारिक रुख नहीं अपनाया, पर सवाल अब भी उठ रहे हैं कि क्या भारत को बीजिंग के साथ संबंध सामान्य करने चाहिए।

दोनों देशों के बीच इस नजदीकी का श्रेय ट्रंप प्रशासन को है। लेकिन 'हाथी और ड्रैगन' के एकसाथ आने के वादे के अलावा, दोनों देशों को सार्थक बातचीत से पहले अब भी कई बड़ी बाधाओं को दूर करना होगा। मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारत-चीन संबंधों में व्यक्तिगत रूप से रुचि ली और 2018 तक पांच बार पड़ोसी देश का दौरा किया। लेकिन 2020 में लद्दाख के गलवान में हुए सीमा संघर्ष ने इस पर विराम लगा दिया और उसके बाद चीन का दौरा करने में मोदी को सात साल लग गए। सीमा का मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों के मूल में बना हुआ है। दोनों देशों के दसियों हजार सैनिक अब भी विवादित सीमाओं पर तैनात हैं, हालांकि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बातचीत जारी है। रविवार की बैठक के बाद चीन और भारत, दोनों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और 'अपने मतभेदों को विवाद में न बदलने' की बात कही। यह नेक काम है, और संभव भी, लेकिन आसान नहीं है।

भारत के लिए जमीनी हकीकत अब भी नहीं बदली है। पश्चिमी देशों के साथ उसके बुनियादी आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं, और अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भू-राजनीतिक दृष्टि से, पिछले दो दशकों में विभिन्न अमेरिकी प्रशासनों ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी विस्तार के विरुद्ध अमेरिका की 'धुरी' के रूप में देखा है। दिल्ली कई अन्य बहुपक्षीय मंचों का भी हिस्सा है, जिन्हें चीन-विरोधी और रूस-विरोधी माना जाता है। भारत के साथ ट्रंप का व्यवहार उन अनेक उतार-चढ़ावों में से एक है, जो दोनों लोकतंत्रों ने झेले हैं। यह वास्तविकता है, आने वाले महीनों में यह देखना बाकी है कि क्या ट्रंप टैरिफ और व्यापार के मामले में भारत के प्रति अपने रुख को नरम और तर्कसंगत बनाते हैं। भारत के लिए, बांग्लादेश की अंतिम मोर्चेबंदी से सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं, इसलिए स्थिति गंभीर है। कुल मिलाकर, भारत-चीन की जुगलबंदी की गति निर्धारित करने में अमेरिका की बहुत अधिक भूमिका होगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

ओशो

अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से अपनी शंकाओं को लेकर प्रश्न पर प्रश्न करते चले गए, लेकिन उन्हें बात तब समझ आई, जब उनका मन पूरी तरह प्रश्नों से खाली हो गया था।

प्रश्नों से भरे मन को खाली कर दो

अर्जुन के प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। किसी के भी प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, वैसे ही मनुष्य के मन में प्रश्न लगते हैं। और जैसे झरने नीचे की तरफ बहते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन प्रश्नों के गड्ढों को खोजता है। कृष्ण जैसा व्यक्ति भी मौजूद हो, तो भी प्रश्न उठते ही चले जाते हैं। और शायद उन्हीं प्रश्नों के कारण अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को भी देख पाने में समर्थ नहीं हैं। और शायद उन्हीं प्रश्नों के कारण अर्जुन शुरुआत में उनके उत्तर को ठीक से समझ नहीं पाते। जिस मन में बहुत प्रश्न हों, वह उत्तर को समझ नहीं पाता है, क्योंकि जब उत्तर दिए जाते हैं, तब वह उन्हें सुनता नहीं, अपने प्रश्नों को ही भीतर गुंजाता चला जाता है। श्रीकृष्ण कहते जरूर हैं, पर अर्जुन समझते नहीं।

दुविधा है, लेकिन ऐसी ही स्थिति है। जब तक प्रश्न होते हैं मन में, तब तक उत्तर समझ में नहीं आता है। और जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं, तो उत्तर समझ में आ जाते हैं। प्रश्न से भरा हुआ मन हो, साक्षात उत्तर बनकर भगवान श्रीकृष्ण भी सामने खड़े हों, तो भी समझ के बाहर है। और मन से प्रश्न गिर जाएं, तो सामने पड़ा पत्थर भी उत्तर बन जाता है। निष्प्रश्न मन में उत्तर का आगमन होता है। प्रश्न भरे चित्त में उत्तर के आने की जगह भी नहीं होती। हमनी भीड़ होती है कि उत्तर के लिए प्रवेश का मार्ग भी नहीं मिलता है। अर्जुन पूछते चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि समझने की कोशिश न करते हों, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार समझने की कोशिश ही समझने में बाधा बन जाती है। जब भी मन कोशिश करता है, तो तनावग्रस्त हो जाता है, खिंच जाता है। उस खिंची हुई, तनी हुई हालत में कुछ भी समझ में नहीं आता है। समझने की कोशिश भी जहां नहीं है, सिर्फ पी लेने का भाव है, पूछने का भी जहां ख्याल नहीं है, जो मिल जाए, उसे प्राणों में संजो लेने की आकांक्षा है। खींच लेने की भी आतुरता नहीं है कि यहीं मैं खींच लूं, जान लूं, पा लूं। द्वार खोलकर प्रतीक्षा करने की जहां हिम्मत है, वहां उत्तर चुपचाप, बिना पदचाप किए भीतर चला आता है। और बड़े-बड़े प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मन बड़े-बड़े प्रश्न खड़े कर देता है। लेकिन जब तक मन प्रश्न खड़े करता रहता है, तब तक छोटा भी उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि मन ही बाधा है।

अर्जुन प्रश्नों की कतार खड़ी करते हैं। इसके पहले कृष्ण उत्तर देते रहते हैं। वह घूम-घूमकर नए-नए प्रश्नों के नाम से फिर पुरानी-पुरानी बातें खड़ी कर लेते हैं। वह फिर पूछते हैं। वह पूछते हैं, 'हम क्या हैं?' प्रश्न का अंत नहीं होता, हालांकि समस्त प्रश्नों का अंत ब्रह्म के प्रश्न के साथ हो जाता है। असल में हमारा मन जब भी एक जवाब पाता है, तो उस जवाब का एक ही उपयोग करना जानता है, वह उससे दस सवाल बना लेता है। पूरे मनुष्य जाति के मन में इतिहास नए-प्रश्नों का इतिहास है। एक भी उत्तर आदमी खोज नहीं पाता।

खुले मन से सीखें

जीवन में कई प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमें खोजना चाहिए, लेकिन उत्तर खोजने में स्वयं को केवल सवाल पूछने वाला ही न बनाएं, बल्कि उत्तर देने वाला भी बनें। मन को प्रश्नों से भरे हुए हैं, समझते हैं कि हम सब कुछ सीख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ज्ञान खाली मन में अपना घर बनाता है। इसलिए खुले मन से सीखें। इस प्रकार आप बिना जोर दिए किसी भी ज्ञान को अपने भीतर ले आएंगे।

सूत्र

दूसरा पहलू

हाल में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में बताया गया है कि आलू की उत्पत्ति टमाटर और एटप्यूबरोसम से मिलकर हुई है।

क्या आलू की उत्पत्ति टमाटर से हुई है

पकाकर, उबालकर, मसलकर, भूंजकर, तलकर न जाने किस-किस रूप में हम आलू का खाने में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में हर साल 35 करोड़ टन से ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। गेहूं और धान की अपेक्षा यह कम जगह में ही अच्छी उपज देता है। विभिन्न वातावरणों में पैदा होने की क्षमता ने इसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी बना दिया है। लगभग हर कोई आलू खाता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन अब वैज्ञानिक कह सकते हैं कि यह टमाटर से आया है।

एलेक्स रॉबर्ट्स जिल

हाल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आलू की उत्पत्ति करीब नौ करोड़ वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका के आलू जैसे पौधों के समूह एटप्यूबरोसम और जंगली टमाटर के पौधों की आनुवंशिक सामग्री के संयोजन से हुई होगी। इस संकरण प्रक्रिया के कारण कंद के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई, जिसे मनुष्य ने खोज निकाला। चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के शोधार्थी और अध्ययन के प्रमुख लेखक झियांग झेंग ने कहा, 'हमने विश्लेषण किया और पाया कि आलू दो पौधों, टमाटर और एटप्यूबरोसम का बच्चा है।' वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक देखा कि जमीन के ऊपर, आधुनिक आलू के पौधे एटप्यूबरोसम के उपसमूह से काफी मेल खाते हैं, लेकिन एटप्यूबरोसम में कंद नहीं होते, इसलिए आलू, टमाटर से ज्यादा मिलते-जुलते प्रतीत होते हैं, दोनों ही साझा जीनस सोलनम के अंतर्गत आते हैं। यह हैरान करने वाली बात थी कि आलू एक पौधे से मिलते-जुलते क्यों थे, लेकिन दूसरे पौधे से उनका रिश्ता क्यों था?

हजारों साल पहले उगाए गए आलू की उत्पत्ति का पता लगाने वाले वर्जीनिया टेक के बागवानी विशेषज्ञ रिचर्ड वेइलबस ने कहा, 'अब हम पहले की तुलना में बेहतर तरीके से जानते हैं कि आलू कहां से आए हैं।'

अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पहेली को सुलझाने के लिए तीन बहान वंशों (टमाटर, एटप्यूबरोसम और आलू के पौधे व उनके जंगली रिश्तेदारों) के 128 जीनोम का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि आधुनिक आलू का एक निश्चित वंश था, आठ से नौ करोड़ साल पहले यह संकर टमाटर और एटप्यूबरोसम वंश से उत्पन्न हुआ था और इसी से कंदों की उत्पत्ति हुई। इस संकरण ने संभवतः बाद की आलू प्रजातियों (आज 100 से ज्यादा आलू की प्रजातियां हैं) को उच्च एंडीज पर्वतमाला में, जहां ठंडी जलवायु प्रचलित थी, विविधता लाने और अपना विस्तार करने में सक्षम बनाया। हजारों साल पहले उगाए गए आलू की उत्पत्ति का पता लगाने वाले वर्जीनिया टेक के बागवानी विशेषज्ञ रिचर्ड वेइलबस ने इस अध्ययन को 'जीनोमिक्स का एक रचनात्मक उपयोग' बताते हुए कहा, 'अब हम पहले की तुलना में बेहतर तरीके से जानते हैं कि आलू कहां से आए हैं।'

©The New York Times 2025

आंकड़े

सर्वाधिक पेटेंट

अपने सामान का प्रचार करने के लिए दुनिया भर के देश संबंधित सामान का पेटेंट कराते हैं। इस मामले में चीन सबसे ऊपर है।

चीन	1,940
अमेरिका	1,780
जापान	1,560
जर्मनी	1,430
दक्षिण कोरिया	1,390

आंकड़े पेटेंट के, 1240 पेटेंट के साथ भारत सातवें नंबर पर है। | स्रोत : WIPO TTR, 2025

भाद्रपद के अंतिम मंगलवार के दिन हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण कर त्रेतायुग में रावण और द्वापर युग में भीम का अहंकार तोड़ा था।

अहंकारनाशक बुढ़वा मंगल

भाद्रपद के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान ने इस दिन अपने परमभक्त हनुमान जी के जरिये त्रेतायुग में रावण, तो द्वापर युग में भीम का अहंकार तोड़ा था। इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा का भी विधान है।

एक कथा के अनुसार, हनुमान जी जब सीता माई को खोजते हुए लंका पहुंचे तो रावण ने बंदर काकर उनका अपमान किया। रावण के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भी उन्होंने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था। जिस दिन हनुमान जी ने यह रूप धारण किया था, उस दिन भाद्रपद मास का मंगलवार था। उसी दिन उन्होंने अपनी पूंछ से लंका को जलाकर लंकापति रावण का घमंड चकनाचूर किया था। दूसरी कथा के अनुसार, महाभारत काल में हजारों हाथियों के समान बल वाले भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर दिखाई दिया। घमंड भरी आवाज में भीम ने वानर से कहा कि रास्ते से अपनी पूंछ हटाओ। हनुमान जी ने कहा, तुम ही हटा दो, लेकिन भीम पूंछ को हिला भी न सके। भीम समझ गए यह कोई साधारण वानर नहीं, साक्षात हनुमान जी हैं। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, अब अपने बल का घमंड नहीं करूंगा।

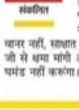

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 सितंबर, 1952

रूस ने निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव ठुकराया

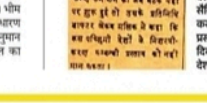

रूस ने निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव ठुकरा दिया

लन्दन, 1० अगस्त।

संयुक्त राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण कमीशन की अब बैठक शुरू हुई तो उसके अध्यक्ष डा. जेकब मलिक ने कहा कि रूस पश्चिमी देशों के निशस्त्रीकरण प्रस्ताव को नहीं मान सकता।

संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण कमीशन की न्यूयॉर्क में हुई बैठक के दौरान पश्चिमी देशों की ओर से रखे गए सैनिकों की संख्या सीमित करने और निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को रूस ने ठुकरा दिया है और कहा, यह हम देशों के रुख को देखेगा।

ताकि बना रहे निवेशकों का भरोसा

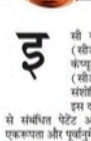

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट में उच्च स्थान प्रगति का सूचक है। अब सीआरआई के दिशा-निर्देश चुनौतियों के समाधान का रोडमैप बनेंगे।

विकास आसावत | **तकनीक**

इसी वर्ष जुलाई में पेटेंट ऑफिस (सीजीपीडीटीएम), भारत सरकार ने कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों (सीआरआई) की जांच के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दस्तावेज का उद्देश्य सीआरआई से संबंधित पेटेंट आवेदनों की जांच में स्पष्टता, एकरूपता और पूर्वानुमेयता को बढ़ाने के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप परीक्षण को लागू करना है। इन दिशा-निर्देशों को अनुपालन से देश-विदेश के कंप्यूटिंग व सॉफ्टवेयर शोधकर्ता और कंपनियों में भारतीय इनोवेटिव इकोसिस्टम की विश्वसनीयता के साथ निवेश की संभावना भी बढ़ेगी।

वर्तमान तकनीकी परिदृश्य जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उसके सबसेट, क्वांटम तथा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए पृथक विस्तृत पेटेंटेबिलिटी व नॉन-पेटेंटेबिलिटी मानदंड जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के तहत इन आविष्कारों को पेटेंट स्वीकृति के लिए इनमें प्रयुक्त न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डाटासेट, प्रशिक्षण विधियों और बेंचमार्किंग विवरणों सहित सख्त डिस्क्लोजर मानदंड को पूरा करना होगा।

मैथमेटिकल मॉडल, बिजनेस मेथड्स, एल्गोरिदम और कंप्यूटर प्रोग्राम को प्राथमिक रूप से नॉन-पेटेंटेबल विषय की श्रेणी में रखा गया है तथा स्पष्ट रूप से सहकार तकनीकी प्रभाव (जैसे डाटा कंप्रेशन पद्धति) प्रदर्शित करने पर ही इन तकनीकों को पेटेंट मिलेगा। किसी आविष्कार में मैथमेटिकल टूल का उपयोग करके रियल टाइम ऑडियो डिवाइस में बैकग्राउंड नॉइज कम करने से बेहतर ऑडियो आउटपुट का मिलना पेटेंटेबल है। रियल टाइम डाटा कैप्चर, मशीन लर्निंग एनालिसिस एंड ऑटोमेटेड अलर्टिंग तकनीक के एकीकृत सिस्टम से विलीय लेनदेन में इंस्टेंट फ्रॉड का पता लगाना भी पेटेंट के योग्य विषय वस्तु है। वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग व ब्लॉकचेन के व्यावहारिक कार्यान्वयन, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, पेटेंट के योग्य हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों जैसे सिक्योर आर्टी आर्किटेक्चर, मेट्रोलॉजी, सेंसिंग डिवाइस के साथ-साथ ड्रग डेवलपमेंट और मटेरियल इंजीनियरिंग में वृहद प्रगति की संभावना को रेखांकित करती है।

गौरतलब है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) वर्ष 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंचा है, जो देश के इनोवेशन इंडेक्स की उत्कृष्ट प्रगति का सूचक है। संशोधित सीआरआई दिशा-निर्देश नीतिगत वातावरण को और मजबूत करेंगे तथा इंडेक्स में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक कारक स्थापित हो सकते हैं।

ज्ञात रहे 2017 के सीआरआई दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधात्मक फलूं ज्यादा था और फोकस मुख्यतः हार्डवेयर लिंकेज पर था, जिससे सामान्यतया सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम-आधारित आविष्कार को स्वीकृति मिलना चुनौतीपूर्ण था। साथ ही सीमित व्याख्या या स्पष्टीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्रों में नवाचारों के लिए अनिश्चितता व असमंजस की स्थिति थी।

दिशा-निर्देशों में नवीनता के लिए सात चरणीय और आविष्कारशीलता के लिए पांच चरणीय परीक्षण शामिल हैं। पेटेंट दावे को समझना, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, दायरा, संदर्भ में प्रासंगिकता, बुनियादी कंप्यूटिंग से आगे (तकनीकी सुधार) इन चरणों का हिस्सा है।

ये दिशा-निर्देश विशेष रूप से एआई कार्यान्वित और अन्य विघटनकारी प्रौद्योगिकी-आधारित आविष्कारों को पेटेंट योग्यता को निर्धारित करने में हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। आवेदक रियल-टाइम प्रॉब्लम को हल करने के लिए विशिष्ट इनेबलिंग डिटेल्स का विवरण प्रदान करें और अस्पष्ट व काल्पनिक भाषा का उपयोग न करें। वहीं उच्च डिस्क्लोजर की बाध्यता के कारण तकनीकी कंपनियां व्यापारिक हित प्रभावित होने के अंदेशे से अपनी मालिकाना जानकारी को साझा करने से हतोत्साहित हो सकती हैं और इस परिस्थिति में उसे पेटेंट से वंचित रहना पड़ सकता है।

नए सीआरआई दिशा-निर्देश एक सकारात्मक और अनुकूल पहल हैं, जो एक आधुनिक और प्रभावी बौद्धिक संपदा व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व तत्परता को दर्शाते हैं। ये दस्तावेज जटिल व अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों पर आधारित आवेदनों को निस्तारित करने का सही रोडमैप नजर आते हैं। दिशा-निर्देश, सार्थक व उपयोगी डिजिटल नवाचार के संरक्षण और अमूर्त विचार मात्र के अस्वीकरण के बीच संतुलन स्थापित करती है। इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से तकनीकी निवेशकों व अनुसंधानकर्ताओं में भारतीय पेटेंट सिस्टम के प्रति विश्वास अधिक गहरा होगा व भारतीय पेटेंट सिस्टम मुख्य वैश्विक व्यवस्था के अधिक नजदीक होगा।

नेतन्याहू का विरोध

वैधानिकता का संकट

ऐसा लगता है कि दुनिया अब इजराइल से तंग आ चुकी है। इजराइल द्वारा गाजा के लोगों पर घोर मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचारों ने जनमत को इजराइल के विरुद्ध कर दिया है, और कई देश अब फि लिस्तीन में उसके कार्यों की खुलेआम निंदा कर रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अविचलित हैं और अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमलों के बाद कभी दुनिया भर में व्यापक समर्थन पाने वाले इजराइल को अब अपने पुराने सहयोगियों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इजराइल-फि लिस्तीनी संघर्ष पर अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहे हैं, और कुछ देश फि लिस्तीनी राज्य के दर्जे को औपचारिक मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं - जो बदलते कूटनीतिक रुझानों का एक स्पष्ट संकेत है।

वैश्विक जनमत में एक महत्वपूर्ण मोड़ गाजा में इजराइल का आचरण रहा है, जिसे अब कई लोग असंगत और तेजी से अक्षम्य मानते हैं। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने भूख से मरते बच्चों और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों की तस्वीरें प्रसारित की हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित रिपोर्टों ने फि लिस्तीनी परिक्षेत्र में अकाल जैसे हालात पर प्रकाश डाला है। अब तक, इस संघर्ष में कम से कम 62,000 लोगों की जान जा चुकी है ह्ल जिनमें से आधी महिलाएं और बच्चे हैं ह्ल और गाजा का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद हो गया है। शुरूआत में जिसे हमास के हमले का सैन्य जवाब माना जा रहा था, उसे अब राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार को बचाए रखना है। दो प्रमुख इजराइली समूहों सहित मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है कि गाजा में इजराइल की कार्रवाई नरसंहार के समान है। इसका विरोध केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। नेतन्याहू सरकार के कई सदस्यों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, और कुछ दक्षिणपंथी अधिकारियों को फि लिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने के कारण विदेशों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

ये कदम विश्व नेताओं में इजराइल को उसकी नीतियों के लिए जवाबदेह ठहराने की बढ़ती इच्छा को दर्शाते हैं, भले ही इसके लिए उनके पुराने गठबंधनों में तनाव क्यों न हो। घरेलू स्तर पर, इजराइली समाज गहराई से विभाजित है। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि 70 प्रतिशत नागरिक नेतन्याहू सरकार को अस्वीकार करते हैं, और कई लोगों का मानना है कि राजनीतिक लाभ के लिए युद्ध को लंबा खींचा जा रहा है। जनता की हताशा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में परिणत हुई है, जिसमें 17 अगस्त को तेल अवीव में एक ऐतिहासिक रैली भी शामिल है, जिसमें तत्काल युद्धविराम और बंधकों की सुरक्षित वापसी की मांग की गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का असर विदेशों में इजराइली नागरिकों और संस्थानों पर भी पड़ा है।

2005 से सक्रिय बहिष्कार, डिवेस्टमेंट, प्रतिबंध (बीडीएस) आंदोलन ने नया जोर पकड़ा है। यूरोपीय किराना दुकानों से इजराइली उत्पाद हटा दिए गए हैं, शिक्षाविदों को सहयोगात्मक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, और इजराइली कलाकारों को दुनिया भर के सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रमों से लगातार वंचित किया जा रहा है। बढ़ती आलोचना के बावजूद, नेतन्याहू अपने रुख पर अड़े हुए हैं, लेकिन उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल इस स्थिति से कैसे निपटता है, यह इस क्षेत्र में शांति और उसके अपने अस्तित्व की संभावनाओं को तय करेगा।

भूराजनीति को प्रभावित करते असाधारण खनिज

बर्मा की औपनिवेशिक खदानों से लेकर भीतरी मंगोलिया के औद्योगिक केंद्रों तक, दुर्लभ धातुओं पर चीन के प्रभुत्व ने इन कभी अज्ञात धातुओं को भू-राजनीतिक प्रभाव के औजारों में बदल दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार, सैन्य रणनीति और तकनीकी शक्ति की संरचना में नया परिवर्तन आया है।

मीलांत इलांगमुआ
लेखक, स्तम्भकार हैं।

इक्कीसवीं सदी की अर्थव्यवस्था की तीव्र पर असल में किसका कब्जा है? आधुनिक रक्षा प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को नियंत्रित करने का सामर्थ्य किन देशों के पास है? पश्चिम की औद्योगिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए अपरिहार्य बाजार पर एक ही देश का प्रभुत्व कैसे स्थापित हो गया?

कहानी वर्षों पर शुरू होती है, जो ऐतिहासिक रूप से टिन, टंगस्टन और दुर्लभ मृदा खनिजों के समृद्ध भंडारों से संपन्न क्षेत्र है। औपनिवेशिक काल के दौरान, ब्रिटिश और बाद में जापानी हितों ने इन संसाधनों का दोहन किया, स्थानीय आबादी या स्थानिक क्षरण की परवाह किए बिना धन का दोहन किया। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टंगस्टन निष्कर्षण ने जापान की युद्ध मशीन को सीधे विस्तारित किया, जो दर्शाता है कि कैसे रणनीतिक खनिजों पर नियंत्रण सैन्य लाभ में तब्दील हो सकता है। हालांकि, उन शुरूआती दशकों में भी, ऐसी धातुओं का निष्कर्षण और परिवहन भू-राजनीतिक जटिलताओं से भरा था: जंगल युद्ध, जापानी रेल नेटवर्क और स्थानीय प्रतिरोध ने यह सुनिश्चित किया कि खनिज संपदा का पूरी तरह से दोहन शायद ही कभी हो पाया, जिससे शोषण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा खाका तैयार हुआ जो बाद के दशकों में भी जारी रहा।

दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) – निओडिमियम, डिस्प्रोसियम और प्रेजेडायमियम सहित सत्रह धातुओं का एक समूह – का नाम भले ही भ्रामक हो, फिर भी स्थायी चुम्बकों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और लड़ाकू विमानों के निर्माण में वे अपरिहार्य हैं। चीन की पकड़ ढीली करने के पश्चिमी प्रयासों के एक दशक से भी ज्यादा समय के बावजूद, बीजिंग अभी भी अडाणी बना हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2019 में जियांगशी प्रांत में एक दुर्लभ मृदा चुम्बक कारखाने की यात्रा को वाशिंगटन पोस्ट ने व्यापक रूप से रुक्ति प्रदर्शन के रूप में व्याख्यायित किया, जो वाशिंगटन को इन महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए बीजिंग पर अपनी निर्भरता की एक जानबूझकर याद दिलाने वाला प्रयास था।

चीन की रणनीतिक दूरदर्शिता का पता देंग शियाओपिंग द्वारा 1992 में आंतरिक मंगोलिया के बाओटौ में दिए गए इस कथन से मिलता है: ह्लमध्य पूर्व में तेल है, चीन में दुर्लभ मृदाएँ हैं ह्व देंग का यह कथन दूरदर्शी साबित हुआ, जिसने खनन, पृथक्करण, शोधन और चुम्बक उत्पादन को शामिल करते हुए एक सावधानीपूर्वक संचालित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का पूर्वाभास दिया। हजारों लघु-स्तरीय खदानों को समेकित करके और मूल्य श्रृंखला को लंबवत रूप से एकीकृत करके, चीन ने कस्बे खनिज संपदा को भू-राजनीतिक उत्तोलक में बदल दिया है। जैसा कि राइजिंग नॉनफेरस मेटल्स शेयर कंपनी के प्रमुख जिनांग झांग ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा, ह्लअंतर्राष्ट्रीय बाजार निकट भविष्य में चीन की दुर्लभ मृदा आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर रहेंगे।

शक्ति के इस संकेंद्रण ने पश्चिमी देशों को प्रतिक्रियात्मक संघर्ष के लिए मजबूर कर दिया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कैलिफोर्निया में केवल एक सक्रिय दुर्लभ मृदा खदान, माउंटेन पास, है, जो निओडिमियम और प्रेजेडायमियम का निष्कर्षण करती है, लेकिन प्रसंस्करण के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने देखा, घरेलू चुंबक निर्माण सुविधा के निर्माण के लिए एमपी मैटेरियल्स में पेंटागन का 400 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश एक दुर्लभ आयात निर्भरता से ह्लअमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला स्वतंत्रता को गति देगा है। फिर भी, ऐसे उपायों के सामने भी कठिन तकनीकी और आर्थिक बाधाएँ हैं, क्योंकि चीन न केवल निष्कर्षण, बल्कि डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण और चुंबक उत्पादन में भी दबदबा रखता है, खनन के 70 प्रतिशत, पृथक्करण और प्रसंस्करण के 90 प्रतिशत, और वैश्विक चुंबक निर्माण के 93 प्रतिशत को नियंत्रित करता है।

पश्चिमी शक्तियों ने अपरंपरागत भौगोलिक क्षेत्रों में वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की है। ग्रीनलैंड, जहाँ दुर्लभ मृदा के कुछ सबसे बड़े अप्रयुक्त भंडार हैं, ने ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिकी रुचि को आकर्षित किया है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी ग्रीनलैंड में प्रस्तावित टैन्बीज खनन एक दूरस्थ फर्जाड में टैंटलम, निओबियम, ज़िरकोनियम और आर्काई (रसायन ऊर्जा) निकालेगी, जिसके लिए एक तैरते हुए गहरे पानी के बंदरगाह, श्रमिकों के लिए आवास और पर्याप्त ऊर्जा अवसंरचना की आवश्यकता होगी। क्रिटिकल मेटल्स कॉर्प के सीईओ टोनी सेज ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प का उद्देश्य ग्रीनलैंड का अधिग्रहण नहीं था, बल्कि अमेरिकी निगमों और रक्षा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने वाले खनन सौदों तक पहुंच को बढ़ावा देना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी घरेलू अपशिष्ट धाराओं को महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया है। कोलोराडो स्कूल ऑफ माइन्स के 2025 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि रुमीजूठा खनन कार्यों से उप-उत्पादों की थोड़ी मात्रा भी ह्लग्रत करने से अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों के लिए शुद्ध आयात निर्भरता में काफी कमी आएगी ह्व पंद्रह तत्वों के लिए - जिनमें दुर्लभ मृदा, वैलियम और जर्मेनियम शामिल हैं - संभावित उप-उत्पादों का एक प्रतिशत से भी कम प्राप्त करना आयात की भरपाई कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त घरेलू भंडार पर प्रकाश डाला जा सकता है। हालाँकि, इन निष्कर्षों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य कार्यों में बदलना एक कठिन चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए रुबहुत अधिक अनुसंधान, विकास और नीति की आवश्यकता है। चीन ने अपने दुर्लभ मृदा प्रभुत्व का एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक साधन के रूप में उपयोग किया है। अप्रैल 2023 में, बीजिंग ने सात दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिससे अमेरिका और जापान की आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हुईं, जिसे व्यापक रूप से अमेरिकी टैरिफ की प्रतिक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया गया। सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र की महत्वपूर्ण खनिज विश्लेषक, ग्रेयलिन वस्करन ने स्पष्ट किया कि चीन रुकीमतें बढ़ाने के लिए उत्पादन पर अंकुश नहीं लगाता - बल्कि, वह बाजार में प्रभुत्व का इस्तेमाल करके इन संसाधनों पर अपना प्रभाव बनाए रखता है और उन्हें हथियार बनाता है। ऐसे उपाय इस बात की पुष्टि करते हैं कि दुर्लभ मृदा खनिज न तो केवल वस्तुएँ हैं और न ही पारंपरिक संसाधन, बल्कि ये ऐसे उपकरण हैं जो गठबंधनों, आपूर्ति नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों को नया रूप दे सकते हैं।

पश्चिमी प्रतिक्रियाएँ असमान रही हैं। अमेरिका ने पेंटागन समर्थित परियोजनाओं में निवेश किया है, टैरिफ लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की संभावनाएँ तलाशी हैं, जबकि यूरोपीय संघ और जापान पुनर्चक्रण, भंडारण और घरेलू विकास पर जोर दे रहे हैं। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ऋ ने अपनी 2025 महत्वपूर्ण खनिज कार्य योजना में विविधीकरण, पता लगाने की क्षमता, सतत खनन और नवाचार पर जोर दिया है, और ह्लमहत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में गैर-बाजार नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न खतरे को स्पष्ट रूप से पहचाना है। फिर भी, जैसा कि टेकनोलॉजी मैटेरियल्स रिसर्च के संस्थापक वैरेक हैच ने कहा, ह्लव्यापार पश्चिमी कंपनियों का मंत्र हमेशा "किसी भी कीमत पर सबसे कम लागत' रहा है ह्व यदि कम लागत वाले विकल्प उपलब्ध हैं, तो आप उच्च लागत वाले उत्पादक से क्यों खरीदेंगे?ह्व

चीन की औद्योगिक महारत को दोहराने के प्रयासों को तकनीकी और ऐतिहासिक जड़ता, दोनों का सामना करना पड़ रहा है। व्लूमबर्ग ने बताया कि दुर्लभ मृदा पृथक्करण के लिए महत्वपूर्ण विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया, हालाँकि मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित की गई थी, पर्यावरणीय और नियामक बाधाओं के कारण घरेलू स्तर पर छोड़ दी गई, जिससे चीनी इंजीनियरों को दशकों तक इस तकनीक में निपुणता हासिल करने का मौका मिला। 1950 और 2018 के बीच, चीन ने 25,000 से अधिक दुर्लभ मृदा पेटेंट दायर किए, जो अमेरिकी पेटेंट से 150 प्रतिशत से अधिक है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, जैविक और हरित-तकनीकी विकल्प, जैसे कि दारुपा द्वारा वित्त पोषित एमबर परियोजना, जिसमें आरईई को संसाधित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, औद्योगिक रूप से मापनीय होने में अभी वर्षों लगेंगे।

वाशिंगटन पोस्ट ने 2025 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि जहाँ अमेरिका ग्रीनलैंड और घरेलू खनन पहलों को आगे बढ़ा रहा है, वहीं चीन ने नए लाइसेंसिंग और रिपोर्टिंग नियमों के जरिए दुर्लभ मृदा खनिजों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है, और पर्यावरण संरक्षण के दिखावटी आवरण में निगरानी को केंद्रीकृत कर दिया है। यह एक घोर विरोधाभास को रेखांकित करता है: केवल प्रचुरता ही रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान नहीं करती। असली लाभ प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला प्रशासन पर नियंत्रण में निहित है, ने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चीन ने व्यवस्थित रूप से निवेश किया है और विशेषज्ञता को समेकित किया है।

दुर्लभ मृदा खनिज प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और सैन्य शक्ति के संगम पर प्रभाव के साधन बन गए हैं। जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने देखा, दशकों की राज्य योजना, तकनीकी महारत और बाजार में हेरफेर को देखते हुए, चीन की पकड़ को तोड़ना चुनौतीपूर्ण होगा।

हिमालयी आपदाओं के सबक

यह आम जनता और विशेष रूप से सत्ताधारी वर्ग के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि वे प्रकृति के सौंदर्य के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी संसाधनों के अनियंत्रित दुरुपयोग और अतिदोहन, विज्ञान की उपेक्षा का परिणाम है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है।

वी के बहुगुणा
लेखक, आईसीएआरई के पूर्व डीजी हैं।

प्रकृति का सौंदर्य ईश्वर की एक कला है" और भगवद गीता में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जो हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करने और प्रकृति व मानवीय भावना के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। बादल फटने, ग्लेशियरों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन तथा 2025 के मानसून के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भूगोल पर अनियंत्रित हमले के कारण होने वाली अन्य वायुमंडलीय गड़बड़ियों के कारण बार-बार आने वाली अचानक बाढ़ और जान-माल की विनाशकारी क्षति हृदयविदारक है।

यह आम जनता और विशेष रूप से सत्ताधारी वर्ग के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि वे प्रकृति के सौंदर्य के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी संसाधनों के अनियंत्रित दुरुपयोग और अतिदोहन, विज्ञान की उपेक्षा का परिणाम है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस वर्ष तीन हिमालयी राज्यों में जून 2025 से सामान्य से कहीं अधिक वर्षा हुई है। मानसून के दौरान पश्चिमी विक्षोभ में अब उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जो आमतौर पर सर्दियों और वसंत ऋतु में देखा जाता है। धराली, हर्सिल, थराली, सबाना चट्टी, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और सोलन किन्नवाड़ जैसे पहाड़ियां और कई अन्य स्थान चरम मौसम की घटनाओं - बादल फटना, अचानक बाढ़, भूस्खलन और भूस्खलन - का सामना कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, समुदायों को विस्थापित किया है और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचाया है, जो इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है।

वैज्ञानिक इस विसंगति को आर्कटिक और पश्चिम एशियाई वर्मीस से जोड़ते हैं, जिसने उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे हिमालय में वर्षा तेज हो गई है। जून 2025 में मानसून के मौसम की शुरूआत के बाद से, हिमालय को लगातार बारिश का सामना करना पड़ रहा है, उत्तराखंड में औसत से 421 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। अकेले हिमाचल प्रदेश में अगस्त के मध्य तक 276 मौतें, 336 घायल और 37 लोग लापता दर्ज किए गए, जिससे केवल 20 दिनों के भीतर 739 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। पूरे क्षेत्र में, भारत और पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 280 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलाकर 130 से ज्यादा मौतें हुई हैं और अभी भी कई लोग लापता हैं। इस बाढ़ ने घरों, होटलों, दुकानों और सड़कों को टनों कीचड़ और मलबे में दबा दिया, जिससे कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं।

भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के बचाव अभियानों ने 150 से ज्यादा लोगों को निकाला और कई जीवित बचे लोगों को बचाया। अगर हम उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय स्थलों में विकास के पैटर्न और पर्यटकों की आमद को देखें, तो विकास उन बाहरी ताकतों द्वारा किए गए घोटालों और रैकेट का दर्जा हासिल कर रहा है, जो स्थानीय राजनेताओं, नौकरशाही और भोले-भाले स्थानीय लोगों की मदद से नाजुक पारिस्थितिकी का शोषण करके अमीर बनने की कोशिश में लगे हैं।

जहाँ तक कारणों की बात है, यह सर्वविदित है कि जलवायु परिवर्तन ने मानसून की तीव्रता को बढ़ा दिया है, क्योंकि गर्म हवा में नमी ज्यादा होती है (प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर 7 प्रतिशत तक अधिक)। हिंद महासागर और अरब सागर के गर्म होने से वायुमंडलीय नमी बढ़ गई है, जिससे अचानक और तेज बारिश हो रही है। ग्लेशियरों के पीछे हटने और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पर्वतीय इलाकों में और अस्थिरता आई है, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं।

असंतुलित अनियोजित विकास और प्राकृतिक वनों और पर्यावरण के क्षरण से स्थिति और भी जटिल हो गई है। इसके अलावा, अनियमित शहरीकरण, वनों की कटाई, और गलत तरीके से बनाई गई (गलत तरीके से बनाई गई क्योंकि विकास होना तो चाहिए लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी होना चाहिए) बुनियादी ढाँचा परियोजनाएं जैसे जलविद्युत बाँध और चार लेन वाले राजमार्ग, इलाकों की अनुचित कटाई और भूवैज्ञानिक पहलुओं की मदद से पारिस्थितिकी और पृथिवीज्ञान आधारित क्षेत्रीय विकास योजनाएँ तैयार करनी चाहिए और लोगों को संवेदनशील इलाकों से हटाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी/सहायक नदियों/उप-सतही जल चैनलों का कोई प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो और लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर जल निकासी बनी रहे। वन प्रबंधन और विशेष रूप से वनरोपण कार्यक्रमों को वृक्षारोपण से पहले झाड़ियाँ लगाकर, जलभृतों को पुनः भरकर और अपवाह में कमी लाकर इलाकों को स्थिर करने के लिए सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, स्थानीय स्तर पर आपदा बचाव केंद्रों की स्थापना और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार और नियमित अभ्यास के माध्यम से सामुदायिक लचीलापन विकसित करना। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना जो मौसम के मिजाज पर नजर रखे और किसी भी आपात स्थिति के लिए पहले से तैयारी करे।

हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में हिमालय को देवताओं का निवास माना जाता है और गंगा जैसी नदियाँ दिव्य हैं। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का अंधाधुंध दोहन भारतीय परंपराओं में निहित आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान के सिद्धांत को धोखा देता है। यह आपदा हम सभी से पूछती है। चारा हिमालय के प्रति अपनी आध्यात्मिक श्रद्धा को आधुनिक विकास की माँगों के साथ कैसे संतुलित कर सकता है और जितनी जल्दी सरकारी तंत्र और स्थानीय सामाजिक व राजनीतिक नेता इसे समझेंगे, उतना ही बेहतर होगा।

आप की बात

ट्रंपी दुनिया से नहीं डरेंगे

चीन के तियानजिन में ओरों के साथ शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का एक साथ एकत्रित होना और आपसी सहयोग के लिए तैयार रहना ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प के लिए एक इशारा रहा है कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। भले ही अमेरिका का घुसपैठिया पाक वहां जरूर मौजूद था, फिर भी तीन शक्तियों के सामने वो अपने आप ही गिल्टी हो रहा था. बस वही पुरानी घिसीपिटी बातें ही दोहरा रहा था। जबकि भारत ने बेबाक तरीके से आतंकी, उनके आकाओं/प्रायोजकों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की बात रखी जिसका सभी ने समर्थन किया। पुतिन व मोदी की कार में हुई गुप्त बात पर बनी इस सस्पेंस का असर अमरीका पर जरूर पड़ेगा साथ ही पाक तो यह देखकर सन्न ही रह गया होगा. वैसे यह सम्मिट एशिया की शांति के लिए जरूर सफल होगी। क्योंकि एशिया में भारत,रूस और चीन तीनों ही बड़ी शक्तियां हैं। और जब तीन बड़ी शक्तियां एक होकर रहेंगी तो बाहरी "महाशक्ति" भी एशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यूं भी तीनों की दोस्ती अमेरिका को जरूर इस बात से इंगित करती है कि "हम तीनों ट्रम्पी दुनिया (थ्रैस-डपट) से नहीं डरेंगे. मसलन एशियाई शक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा और अपना व्यवहार बदलाव भी पड़ेगा।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

लोकल फॉर वोकल

अमेरिका के साथ छिड़े टैरिफ वार के बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के मन में स्वदेशी प्रेम जगाने को लेकर विशेष सम्भीर दिखाई दे रहे है कारण उन्होंने एक बार फिर से सभी देशवासियों को दिल से यही बात कही है कि गर्व से कहो हम सब स्वदेशी है एवं स्वदेशी वस्तुएं ही इस्तेमाल करते हैं। हमें अब इसी भाव लेकर आगे चलना है कि अब हमारा एक हि मंत्र रहेगा लोकल फार लोकल। एक ही रास्ता आत्म निर्भर भारत।वहां वे यह भी कहते हैं कि अब इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम है तथा आने वाले दिनों में बहुत सारे त्यौहारों की भी रौनक होने वाली है, अतः हमें इन त्योहारों के दौरान स्वदेशी की बात कभी भी नहीं भुलनी है कारण उपहार वहीं जो भारत में बना हो,पहनावा वही जो अपने देश में बुना हो एवं सजावट वहीं जो देश में बने सामानो से हो। रोशनी भी वही जो भारत में ही बनी हो झालरों से हो। अतः कह सकते हैं कि जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा विशेष कहा जा सकता है, अतः हम भारतीयों का भी अब एक ही उद्देश्य,एक हि नारा होना चाहिए कि हम देश में बनी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें एवं विदेशी वस्तुओं का मोह छोड़ कर उनका बहिष्कार करें एवं देश के निमार्ता निर्देशकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें।

- मनमोहन राजावत , शाजापुर

दोहरा चरित्र

देश में अराजकता पूर्ण वातावरण बनाने के उद्देश्य से बिहार में अपनी राजनीतिक धरती तलाश रही कांग्रेस की यात्रा का कोई असर जनमानस पर पड़ा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, किन्तु इतना अवश्य है कि यात्रा के संयोजकों के दोहरे चरित्र का खुलासा हो गया। पैसे देकर यात्रा में बुलाई गई भीड़ से यह भी सिद्ध हो गया कि औरों पर भ्रष्टाचार और वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद भी भ्रष्टाचार की दलदल में कितनी धंसी है। इस यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि लम्बे समय तक सत्ता सुख भोगने वाले परिवारों को सत्ता से बाहर रहना कितना अखरता है तथा उन्हें किस हद तक मानसिक रूप विक्षिप्त कर सकता है। यात्रा के दौरान शब्दिक मर्यादा का उल्लंघन तथा बिना पुष्ट प्रमाणों के संवैधानिक संस्था व देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणी से सिद्ध हो गया, कि सत्ता से दूरी किस प्रकार से वंशवादी सामंती तत्वों की स्थिति जल बिन मछली तुल्य बिजली जैसी सरीखी बना सकती है। भले ही कांग्रेस इस यात्रा के लिए जुटाई गई भीड़ को आधार बनाकर यात्रा कि सफलता पर अपनी पीठ थपथपाये, मगर सत्य यही है कि इस यात्रा से बिहार चुनाव या देश के मतदाता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस यात्रा ने कांग्रेस के युवराज की बुद्धिलब्धि एवं संवैधानिक प्रक्रिया के संबंध में उनकी समझ पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है।

- सुधाकर आशावादी, मेरठ

टैरिफ का हथौड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का जो नया हथौड़ा चलाया है, उसने 25 वर्षों के सामरिक और आर्थिक संबंधों की बुनियाद को हिला दिया है। अमेरिका की अदालत ने इन टैरिफों को अवैध ठहराया था, फिर भी ट्रंप ने इन्हें 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय सेवा क्षेत्र—खासतौर पर एच-1बी वीजा पर काम करने वाले पेशेवरों और छात्रों—को भी सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। यह भारत के लिए केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की परीक्षा है। भारत की सच्चाई यह है कि 35 साल के आर्थिक सुधारों के बावजूद हम अब तक कोई ऐसा वैश्विक ब्रांड खड़ा नहीं कर पाए हैं, जैसा जापान का टोयोटा, कोरिया का सैमसंग या चीन का हुआवे है। क्यों से भारतीय इंजीनियर और कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल जैसे अमेरिकी दिग्गजों को कोडिंग और सेवाएं देकर खड़ा करती रही हैं, लेकिन चीन की तरह वाइबू, वीचैट या टिकटॉक जैसा अपना मंच नहीं बना पाई। सवाल यह है कि हम अब तक दूसरों की तकनीकी ताकत का सहारा क्यों बने हुए हैं और खुद अपनी राह क्यों नहीं गढ़ पाए? ट्रंप की नीतियां हमें चेतावनी दे रही हैं कि अब आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसके लिए केवल नीतिगत बयानबाजी या डींगें हांकने से काम नहीं चलेगा। हमारे भीतर ही गंभीर कमजोरियां हैं।

- विभुक्ति बुपक्या, अधत खाचरोद, उज्जैन

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 168

प्रतिद्वंद्वी से साझेदार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन गए हैं। यह सात वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों में 'सकारात्मक गति' के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान रहे कि लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे हैं। ध्यानचिन में एससीओ बैठक से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात के बाद दोनों पक्षों की ओर से जारी वक्तव्य में जो भाषा सामने आई उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला।

गत वर्ष रूस के शहर कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से जो सद्भावना बन रही है, उसे बढ़ाते हुए दोनों देशों के बयानों में भारत और चीन को 'प्रतिद्वंद्वी नहीं विकास साझेदार' के रूप में प्रस्तुत किया गया और यह जोर दिया गया कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र चाइना डेली के प्रथम पृष्ठ पर एक आलेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 'साझेदारी को भारत-चीन रिश्तों की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है।' यह भी चीन के नज़रिये में बदलाव दर्शाता है। दोनों बयानों में रणनीतिक स्वायत्तता को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संबंधों को तीसरे देश के नज़रिये से नहीं देखा जाना चाहिए। यह इस बात का परोक्ष संकेत था कि भारत को चीन एशिया में अमेरिका से जुड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में न देखे।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के साथ हाथ मिलाकर, गले मिलकर और 45 मिनट की कार यात्रा के दौरान बातचीत के जरिये यह संकेत देने का प्रयास किया कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की उस मांग को मानने के पक्ष में नहीं है जिसमें उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने पर भारत पर लगे दंडात्मक शुल्क में राहत दी जा सकती है।

यह बदलाव स्वागत योग्य है लेकिन इसे वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से तय करने कोशिश की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। यह वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व की अनिश्चित नीतियों का परिणाम है। वास्तव में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन की भव्यता के माध्यम से चीन के नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधनों की पुनर्रचना के अपने उद्देश्य को छिपाया नहीं है। इस सम्मेलन में 20 नेता शामिल हुए, जिनमें तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन भी थे, जो गाजा में अमेरिका-समर्थित इजरायली अत्याचारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शी चिनफिंग के उद्घाटन भाषण में 'समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व' तथा 'समावेशी वैश्वीकरण' जैसे शब्दों का प्रयोग इस बदलते समीकरण को दर्शाता है।

मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच तालमेल को भूराजनीतिक विवशताओं की यथार्थवादी समझ के साथ देखना चाहिए जो इन संबंधों को दिशा दे रही है। यह बात बैठक के बाद भारतीय और चीनी ब्योरों में कुछ अहम अंतर से स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, सीमा विवाद पर भारतीय बयान में 'सीमा मसले का निष्पक्ष, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान, जो द्विपक्षीय संबंधों के समग्र राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े' की बात कही गई। वहीं चीन के बयान में संकेत दिया गया कि सीमा मुद्दे को भारत-चीन संबंधों की समग्र दिशा को परिभाषित नहीं करना चाहिए। उसमें कहा गया कि दोनों पक्षों को 'भारत-चीन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभालना चाहिए' और 'उन्हें ध्यानचिन शिखर सम्मेलन के माध्यम से और ऊंचा उठाना चाहिए।'

चीन ने जवाहरलाल नेहरू की पंचशील नीति का भी उल्लेख किया जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि 70 साल पहले भारत और चीन के नेताओं द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को संजोने और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है जबकि भारत के बयान में पंचशील का जिक्र नहीं था। चीन ने ग्लोबल साउथ के संयुक्त नेतृत्व की बात की, वहीं भारतीय बयान इस पर मौन रहा। वर्तमान समय में अपने-अपने हित के चलते सहयोग की प्रवृत्ति के कारण इन मतभेदों को फिलहाल नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन नज़रिये का यह अंतर भविष्य में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने पर महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।

अमेरिका के कारोबारी झटके का रचनात्मक जवाब

अमेरिका ने भारत से होने वाले निर्यात पर जो शुल्क वृद्धि की है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें व्यापक नीतिगत सुधारों की जरूरत होगी। बता रही हैं अमिता बत्रा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की राजनीति प्रेरित व्यापार नीति के चलते करीब एक महीने पहले भारत के निर्यात पर 50 फीसदी का असाधारण रूप से ऊंचा शुल्क लगाने की घोषणा की गई। अब जबकि जुमाने वाला शुल्क लागू हो चुका है तो भारतीय निर्यातकों को ट्रंप-पुतिन-जेलेंस्की की बैठकों तथा अमेरिका के साथ स्थगित व्यापार वार्ता के नए सिरे से शुरू होने के बाद कुछ सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। अमेरिका भारतीय के प्रमुख निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। खासतौर पर कपड़ा एवं परिधान, सीफूड, रत्न एवं आभूषण जैसी चीजों के लिए, ऐसे में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता जरूरी होगा।

यह बात उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के अलावा ट्रंप द्वारा घोषित लगभग सभी द्विपक्षीय व्यापार समझौते कानून समर्थित नहीं हैं, उनके ब्योरे उलझे हुए हैं और इसलिए उनकी कई तरह की व्याख्याएं की जा सकती हैं। अमेरिका-जापान व्यापार समझौते के क्रियान्वयन में टैरिफ लगाने की 'गलती' और मूल घोषणा के एक महीने बाद यूरोपीय संघ से वाहन आयात पर अमेरिका द्वारा 15 फीसदी टैरिफ का 'सशर्त' अनुप्रयोग, ऐसी अस्पष्टताओं के प्रमाण हैं। धारा 232 के तहत लंबित जांच और निरंतर वार्ता अमेरिकी व्यापार नीति की अनिश्चितता को बताती है। इसके साथ ही अमेरिकी व्यापार संरक्षण भी लागू रह सकता है क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में टैरिफ में जो इजाफा किया गया था उसे जो बाइडन ने कम नहीं किया था। ऐसे में भारत की व्यापार नीति की प्रतिक्रिया दीर्घकालिक नज़रिये पर आधारित होनी चाहिए।

अपनी सबसे प्रमुख प्रतिक्रिया के रूप में भारत को अपने भीतर झांकने के प्रलोभन से बचना होगा। समग्र मांग में योगदान के अलावा निर्यात, विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भी अहम जरिया है। उसके जरिये उत्पादक रोजगार भी बढ़ते हैं। फिलहाल देश के विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी पिछले दो दशक से लगातार घट रही है। विश्व बैंक के मुताबिक 2006 के 17 फीसदी से कम होकर 2024 में यह 13 फीसदी रह गई। इसी अवधि में भारत के कुल वस्तु निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं की हिस्सेदारी भी कम हुई और 2024 में यह करीब 64 फीसदी थी। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो चीन, वियतनाम और मेक्सिको के निर्यात में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 90 फीसदी, 85 फीसदी और 78 फीसदी रही। ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक मूल्य श्रृंखला से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह एकीकरण वैश्विक विनिर्मित वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने में मददगार रहा है। इसमें भारत की हिस्सेदारी दो दशकों से दो फीसदी के आसपास ठहरी रही है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के जरिये विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ाना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। पहले चरण में हमें अपनी प्रमुख उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना में न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) की समीक्षा करनी चाहिए। निश्चित क्षेत्रों जैसे कि ऑटोमोबाइल, ऑटो-पुर्जे और इलेक्ट्रिक वाहनों में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50 फीसदी डीवीए की शर्त का उद्देश्य वैसे तो गहन स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन यह वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसा संभव है कि आवश्यक घरेलू कच्चे माल उपलब्ध न हों, या यदि वे देश में उत्पादित भी होते हैं, तो आमतौर पर महंगे विकल्प साबित होते हैं। इसके चलते समय के साथ छोटे और मझोले घरेलू उत्पादक कारोबार से बाहर हो जाएंगे और बड़े घरेलू उत्पादकों का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। ध्यान रहे कि गत दो वर्षों में देश के कई बड़े वाहन और वाहन कलपुर्जा उत्पादक, योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन हासिल नहीं कर सके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे 50 फीसदी डीवीए और स्थानीयकरण की जरूरतों को पूरा नहीं कर सके।

शुरुआती डीवीए लक्ष्यों को तर्कसंगत रूप से कम स्तर पर रखना और स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता को धीरे-धीरे समाप्त करना उत्पादन लागत को कम करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे कुशल और कम लागत वाले आयातित कच्चे माल का उपयोग संभव हो पाता है। एक ओर इससे तकनीकी प्रसार संभव होता है, वहीं दूसरी ओर आयातित कच्चे माल प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। दीर्घकालिक रूप में यह घरेलू क्षमताओं के निर्माण और तकनीकी उन्नयन की प्रक्रिया को गति देता है, जो सतत विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना के लिए आवश्यक है।

उपरोक्त नजरिये से देखें विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक उदार आयात नीति अत्यंत आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, आयातित कच्चे माल पर शुल्कों में कटौती की जानी चाहिए।

हाल ही में कपास पर आयात शुल्क में की गई कमी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अब जुलाई 2024 के बजट में किए गए वादे और फरवरी 2025 के बजट में सीमित रूप से शुरू की गई प्रक्रिया के अनुरूप शुल्कों की एक व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र में लागू सर्वाधिक तरजीही देशों पर शुल्कों को प्रतिस्पर्धी आसियान अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप लाने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके।

अमेरिका द्वारा अपनी एशिया की ओर झुकाव की नीति की समीक्षा के संकेतों के मद्देनजर, भारत के लिए आयात शुल्कों को कम करना ज्यादा आवश्यक हो गया है। इस नीति के तहत भारत को चीन के संतुलन के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह रणनीतिक आधार कमजोर होता दिख रहा है। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी और व्यापार प्रतिस्पर्धा के जारी रहने की संभावना को देखते हुए, भारत के लिए यह जरूरी है कि वह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के स्थानांतरण और निर्यात-उन्मुख, कुशलता बढ़ाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहे और इसके लिए आयात शुल्कों में कमी मददगार होगी।

भारत को अपने निर्यात बाजारों को और विविध बनाना होगा। यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से अंतिम रूप देना, आसियान एफटीए की समीक्षा करना, और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) में भागीदारी की तैयारी शुरू करना इस दिशा में सहायक होंगे। हाल ही में ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षरित एफटीए के आधार पर भारत यूरोपीय संघ और सीपीटीपीपी दोनों के साथ आगे बढ़ सकता है।

अंततः यह मान लेना चाहिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और आसियान जैसे लगभग सभी प्रमुख मौजूदा और संभावित निर्यात बाजार अपने-अपने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) विकसित कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह अधिक व्यावहारिक होगा कि वह घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र की ओर तेजी से बढ़े, बजाय इसके कि वह एफटीए में रियायतों और लचीलापन की आशा करे। भारत के सामने एक व्यापक सुधार एजेंडा है और समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए।

(लेखिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

शहरी चुनौती कोष को मजबूत ढांचे की जरूरत

भारत के शहर संभावनाओं से भरपूर हैं मगर धन जुटाने के पुराने तौर-तरीकों और अत्यधिक दबाव का सामना कर रहे बुनियादी ढांचे के कारण अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2011 और 2018 के बीच शहरी उपयोगिता ढांचे (रियल एस्टेट को छोड़कर) पर पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल औसतन 0.6 फीसदी रहा है। यह जरूरी रकम का महज एक चौथाई हिस्सा ही है। वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में हुए 74वें संशोधन का लक्ष्य शहरों को 'अपना भविष्य स्वयं तय करने की स्वतंत्रता' देना था मगर यह उद्देश्य अधूरा रह गया है।

इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस साल फरवरी में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में एक बड़े बदलाव की घोषणा की गई जिसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 'शहरों को विकास के केंद्र बनाने', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' जैसे प्रस्ताव लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के साथ शहरी चुनौती कोष (अर्बन चैलेंज फंड या यूएसीएफ) तैयार करेगी। यह 'अधिकार आधारित' अनुदानों से 'प्रदर्शन आधारित' वित्त पोषण तंत्र की तरफ उठाया गया एक बड़ा रणनीतिक कदम है।

भारत की जनगणना किसी इलाके को दो शर्तों पर शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करती है। पहली शर्त, अगर कोई अधिसूचित शहरी स्थानीय निकाय वाला एक वैधानिक शहर है, तो वह शहरी क्षेत्र में आएगा। दूसरी शर्त, कोई क्षेत्र जनगणना शहर हो जो सभी तीन मानदंडों को पूरा करता हो यानी वहां कम से कम 5,000 आबादी हो, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 जनसंख्या घनत्व हो और 75 फीसदी पुरुष कार्य बल गैर-कृषि गतिविधियों में शामिल हो। वर्ष 2027 की जनगणना में इन मानदंडों को लागू करने से ऐसा हो सकता है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 60 फीसदी से अधिक आबादी रहने लगे।

यह आंकड़ा 2011 में जनगणना में दर्ज 31 फीसदी से काफी अधिक होगा। केरल का मामला बिल्कुल अलग है। वहां शहरीकरण की दर वर्ष 2022 में दर्ज 73.19 फीसदी से 2036 में 96 फीसदी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि, ऐसे राज्य भी हैं जहां शहरीकरण की दर काफी धीमी है। इस स्थिति से निपटने के लिए नीति आयोग चार शहर क्षेत्रों- मुंबई महानगर क्षेत्र, वाराणसी, सूरत और विशाखापत्तनम में आर्थिक गतिविधि और भूमि के इस्तेमाल के आधार पर एक नए ढांचे पर काम कर रहा है।

स्पष्ट है कि भारत में शहरीकरण की राह में पेश आने वाली चुनौतियां काफी कम कर आंकी जा रही हैं।

यूसीएफ का ढांचा महत्त्वाकांक्षा और नई सोच को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत 25 फीसदी वित्त पोषण केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा है और शहरों को परियोजना खर्च का कम से कम 50 फीसदी हिस्सा बॉन्ड, ऋणों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाने के लिए कहा गया है। यूसीएफ अधिक प्रभाव एवं राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर निजी निवेश को बढ़ावा देगा और शहरों द्वारा विकास के लिए रकम जुटाने के तरीकों को नए सिरे से परिभाषित करेगा।

बुनियादी ढांचा

विनायक चटर्जी

शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने को लेकर भारत के पिछले अनुभव को देखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2015 में शुरू 'स्मार्ट सिटी मिशन' से स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा मिला मगर निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रही। केवल 6 फीसदी परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी साझेदारियों (पीपीपी) का इस्तेमाल हुआ और 2023 तक केवल 12 फीसदी परियोजनाएं अपना हिसाब-किताब पूरा करने में सफल रहीं जो 21 फीसदी के लक्ष्य से काफी कम है। सामाजिक ढांचे के लिए 80 फीसदी तक सहयोग की पेशकश करने के बावजूद व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के अंतर्गत दो दशकों के दौरान केवल 71 परियोजनाएं मंजूर हो पाईं। अफसरशाही के स्तर पर देरी, त्रुटिपूर्ण अनुबंध और दोषपूर्ण परियोजना अवधि से जुड़े अनुमानों के कारण यह नौबत आई। नगर निगम (म्युनिसिपल) बॉन्ड इस्तेमाल नहीं पाए क्योंकि ज्यादातर शहरी स्थानीय निकाय साख के पैमाने पर खरा नहीं उतरते थे।

यूसीएफ के ढांचे एवं इसकी आपूर्ति मजबूत करने के लिए इन्फ्राविजन फाउंडेशन ने अपने व्यापक शोध एवं क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए है-

1. यूसीएफ को परियोजना नियोजन, परिचालन एवं रखरखाव, सेवा आपूर्ति में परिवोजना की अवधि से जुड़ी सोच शर्तिवा तौर पर शामिल करनी चाहिए और नागरिकों की संतुष्टि को एक प्रमुख घटक मानते हुए इस पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। परियोजनाओं का ढांचा संरचित परिचालन एवं रखरखाव मानकों, सेवा संबद्ध भुगतान और नागरिक केंद्रित निगरानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के लिए वित्त उपलब्ध कराना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि शहरों के नजरिये (बुनियादी ढांचे को उत्पाद के बजाय उन्हें सेवा मानना) को भी बदलने पर ध्यान होना चाहिए।

2. शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश से जुड़े जोखिम समाप्त कर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यूसीएफ को अपने अनुदानों को फर्स्ट लॉस गारंटी, ऋण वृद्धि और राजस्व नुकसान से बचाव के साथ जोड़ना चाहिए। विकास वित्त बैंक नैबफिड द्वारा प्रस्तावित आंशिक क्रेडिट गारंटी फंड नगर निगमों के बॉन्ड में निवेशकों के भरोसे को बढ़ावा देने में एक सहायक भूमिका निभा सकता है।

3. शहरों को स्वयं अपने संसाधन जुटाने में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। विभिन्न नगर निगम सेवाओं के लिए 'उपयोगकर्ता-भुगतान' का प्रावधान करना राजनीतिक रूप से गर्म मुद्दा बना रहा है। जब तक शहर राजस्व संग्रह एवं इनका प्रबंधन पूरी पारदर्शिता ने नहीं करते हैं तब तक निजी निवेशकों में हिचकिचाहट बनी रहेगी।

4. क्षमता निर्माण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। देश के कई बड़े एवं मझोले शहरों में पुख्ता योजना तैयार करने की क्षमता एवं तकनीकी टीम का अभाव है और जटिल शहरी बुनियादी ढांचे का खाका तैयार करने, निविदा जारी करने और प्रबंधित करने की वित्तीय परख नहीं है। परियोजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन मजबूत करने के लिए शहरों को समर्पित परियोजना तैयारी प्रकोष्ठों, तकनीकी मार्गदर्शन और सहज मंजूरी प्रक्रिया के साथ लैस करना जरूरी है।

5. यूसीएफ को जल-सुरक्षित शहर चुनौती या शून्य-अपशिष्ट चुनौती जैसे लक्षित चुनौती कार्यक्रम शुरू करके नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। इनमें प्रदर्शन-आधारित वित्त पोषण और परिणाम-संबद्ध मूल्यांकन ढांचे द्वारा समर्थन होना चाहिए।

6. यूसीएफ को पीएम गति शक्ति या अटल नवीकरण मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं से अलग अपनी एक पहचान बनाकर स्पष्ट राजस्व मॉडल के साथ उच्च प्रभाव वाली नवीन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे पारगमन-उन्मुख विकास केंद्रों, अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अपशिष्ट का मुद्रीकरण करते हैं।

7. संस्थागत स्पष्टता एक और स्तंभ है। यूसीएफ को एक चुस्त और उत्तरदायी निकाय द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सके। इसे एक और टॉप-डाउन योजना बनने से बचना चाहिए और इसके बजाय परियोजना चयन से लेकर निगरानी और मूल्यांकन तक हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा, स्वायत्तता और नवाचार की भावना को बनाए रखना चाहिए।

यदि भारत को 2047 तक वास्तव में विकसित भारत बनना है, तो हमारे शहरों को पहले विश्वसनीय, रहने योग्य और चुनौतियों से निपटने लायक बनना होगा। शहरी चुनौती कोष एक ऐसा प्रेरक बन सकता है जिसका हमें लंबे समय से इंतजार रहा है।

(लेखक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं इन्फ्राविजन फाउंडेशन (टीआईएफ) के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी हैं। इस लेख में टीआईएफ की कार्यक्रम प्रमुख मुतुम चाओबिसाना का भी शोध सहयोग है।)

आपका पक्ष

सरकारी स्कूलों में कड़े सुधार की दरकार

इस समाचार पत्र में प्रकाशित संपादकीय 'सरकारी शिक्षा तंत्र से दूरी' सरकारी स्कूलों का ढर्रा उजागर करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीनतम समग्र मॉड्यूलर सर्वेक्षण ने सरकारी स्कूलों की विफल व्यवस्था को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 से अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति घटी है। ग्रामीण भारत में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 2025 में 58.9 प्रतिशत रह गई, जबकि शहरी इलाकों में यह 38.9 प्रतिशत से घटकर 36.4 प्रतिशत हो गई। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी नए नामांकनों में तेज गिरावट दर्ज हुई है। विडंबना यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर होने वाला खर्च की तुलना में निजी स्कूलों में सात गुना का अंतर है इसके बावजूद निजी शिक्षा की ओर रुझान बढ़ रहा है जबकि निजी स्कूल भी स्तरीय शिक्षा देने में विफल हैं। ये आंकड़े भी चौंकाने वाले है कि 27 प्रतिशत बच्चे निजी कोचिंग पर निर्भर हैं जिनमें शहरी (31 प्रतिशत) और ग्रामीण (25.5 प्रतिशत) दोनों शामिल है। इस गिरावट के पीछे जवाबदेही की कमी, कमजोर अधोसंरचना और शिक्षकों की अनुपस्थिति मुख्य कारण हैं। सरकारी शिक्षकों की अनुपस्थिति 25 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक पाई गई है। इसके विपरीत, निजी स्कूलों में कम वेतन और बिना पेंशन लाभ के बावजूद शिक्षक नियमित रूप से कार्यरत रहते हैं। स्पष्ट है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जवाबदेही और ठोस सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं।

अमृतलाल मारू, इंदौर

विश्व रोबोटिक्स चैंपियनशिप सीरीज 'टेक्नोक्सियन' के दौरान नोएडा के एक स्कूल के प्रतिभागी अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए

स्पष्ट कानूनी ढांचा और नियमावली बने

रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाना स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इसे संतुलित नीतियों और ठोस उपायों के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा और नियमावली बने। केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियां ही इसे चला सकें। नाबालिगों के खेलने पर रोक के साथ डिजिटल साक्षरता और वित्तीय जागरूकता से जुड़े अभियान चलाने चाहिए।

आदित्य राज सोनी, धार

जुआ खेलने वाले ऐप पर रोक लगाना सही

रियल मनी गेमिंग से हो रही युवाओं को मानसिक और आर्थिक नुकसान के कारण सरकार ने इस पर रोक लगाई है। इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड के लिए भी किया जाने लगा था। इसमें कई भ्रामक विज्ञापन जल्दी पैसा बनाने के लिए गुमराह भी कर रहे थे। अब सिर्फ बिना पैसे के ऑनलाइन गेम खेलने की सुविधा जारी रहेगी।

भगवानदास छारिया, इंदौर

जुए की लत से बचाना मकसद

रियल मनी गेमिंग पर रोक का उद्देश्य लोगों को जुए की लत और आर्थिक नुकसान से बचाना है। यह किशोर और कमजोर वर्ग को वित्तीय जोखिम से सुरक्षित रखता है। यह वर्तमान समय में गेमिंग की लत से हो रहे अपराधों को कम करने में सहायक हो सकता है, आउटडोर गेम्स को बढ़ावा मिलेगा जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुधार में सहायक हो सकता है।

सपना कबीरपंथी, पन्ना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में लगभग 800 लोगों की मौत हो गई तथा 2,500 से अधिक लोग घायल हो गए। भारत ने सोमवार को अफगानिस्तान में भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया है और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को और अधिक आपूर्ति का आश्वासन दिया है।